04 - नाम में क्या रखा है: नारी के अस्तित्व का संघर्ष

05 - महिलाओं की बढ़ती उड़ान और सामने खड़ी चुनौतियाँ

06 - अदालत ने चेक अनादरित मामले में दोषी को सजा-मय ब्याज राशि भुगतान...

07 - फिर लौट आया सिनेमा का स्वर्णिम युग!

A Daily News Magazine
इंदौर
रविवार, 08 मार्च, 2026

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 154, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

श्रम और सामर्थ्य

फोटो: गिरीश शर्मा

सुप्रभात

लेडीज रूमाल
मर्दों के रूमाल से
छोटा होता है -
लगभग आधा!
यह एक तथ्य है
यदि इसे प्रश्न की तरह पूछें तो
क्या आधा होता है स्त्रियों का पसीना
या आँखों से झरने वाली वेदना?
क्या आधी होती हैं
परेशानियाँ औरतों की
या कि संघर्ष पुरुषों की बनिस्बत?
क्या इसलिए छोटा होता है
लेडीज रूमाल ताकि रखकर उसे
कहीं घेरी जा सके अपनी जगह कथित
औकात के मुताबिक़?

अभी-अभी देखा मैंने कि
वही छोटा लेडीज रूमाल
फुसफुसा रहा है
औरत के कान में
औरत ने भींच लिया है रूमाल अपनी
मुट्ठी में निचोड़ रही है रूमाल से
नीर भरी दु:ख की बदली झरझर
अब वह औरत सुखायेगी
रूमाल को
और फहरायेगी
उसे हवा में पताका की तरह।

- निरंजन श्रोत्रिय

टी 20 वर्ल्डकप का फाइनल मैच आज

खिताबी भिड़ंत में भारत और न्यूजीलैंड की होगी टक्कर

नई दिल्ली (एजेंसी)। टी-20 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है। कल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग होगी। फाइनल से पहले ही आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 8 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है।

आईसीसी के नोमिनेशन में भारत के संजू सैमसन का भी नाम है। भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी टूर्नामेंट के इतिहास में रिकॉर्ड 15वीं बार फाइनल खेलने उतरेगी। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में मिली पहली वर्ल्ड कप जीत से शुरू हुआ यह सफर भारत को अब तक 7 ट्रॉफियां दिला चुका है। आईसीसी टूर्नामेंट्स (वनडे वर्ल्ड कप + चैंपियंस ट्रॉफी + टी-20 वर्ल्ड कप + वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप) में ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है, जिसने 14 फाइनल में से 10 ट्रॉफियां जीती हैं। 2002 चैंपियंस ट्रॉफी का भारत-श्रीलंका फाइनल बारिश के कारण दो दिन में भी पूरा नहीं हो सका था। इसलिए दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया।

हम एकत्व को नहीं पहचानते इसलिए हो रहे हैं आक्रमण

- जैसलमेर में बोले मोहन भागवत, सद्भावना व एकता पर जोर

कहा-हम बंटे हुए हैं, इसलिए चारों तरफ आक्रमण हो रहे हैं

जैसलमेर (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने सद्भावना व एकता पर जोर देते हुए कहा कि समय बड़ा कठिन है। हम बंटे हुए हैं, इसलिए चारों तरफ आक्रमण हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी खत्म भी नहीं हुआ था। इसी बीच अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम अपने एकत्व को नहीं पहचानते, इसलिए दुनियाभर में कलह थमती नहीं है और युद्ध चलते रहते हैं।

उन्होंने कहा कि लोग मन की करुणा भूल गए हैं और इस सत्य को भूल गए कि हम दिखते अलग-अलग हैं लेकिन हम सब एक हैं। जब हम विविधता को अलगाव की दृष्टि से देखने लगते हैं, तब मतभेद पैदा होते हैं,

इसलिए विविधता को स्वीकार करते हुए भी अपनी एकता को नहीं भूलना चाहिए। संघ प्रमुख जैसलमेर में जैन समुदाय के चादर महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर धर्म सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पहला विश्व युद्ध हुआ, यह फिर से न हो इसलिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। लेकिन वह नहीं चली। फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ। यह फिर से न हो इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। लेकिन अब देख रहे हैं कि क्या हालात हैं। वह अपनी जगह पर है, निष्प्रभावी है। जो युद्ध चल रहे हैं वे थम नहीं रहे।

भागवत ने कहा कि हम सभी भेद और स्वार्थ को तिलांजलि देकर और देश के लिए जीने-मरने को तैयार हो जाए तो हमारा समाज अच्छा बनेगा। भारत विश्वगुरु बनकर एक सुखी-सुंदर दुनिया को जन्म देगा। हम सभी मूल रूप से समान हैं क्योंकि परमात्मा एक ही है। जब समाज में अनेकता का आभास होने लगता है तो अलगाव की स्थिति पैदा होने में देर नहीं लगती। इसलिए हमें सदैव एकता पर ही ध्यान रखना चाहिए।

मप्र में 'क्वींस ऑन द व्हील्स' का आगाज

1400 किमी का सफर और 25 जांबाज महिला राइडर्स, सीएम ने दिखाई हरी झंडी

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश की सड़कों पर अब नारी शक्ति के साहस और रोमांच की गूंज सुनाई देगी। शनिवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'क्वींस ऑन द व्हील्स' के तीसरे महिला बाइकिंग टूर का शुभारंभ किया। महिला दिवस और रंगपंचमी के उल्लास के बीच शुरू हुआ यह सफर न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि देश को यह संदेश भी देगा कि मध्यप्रदेश महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित और सुलभ है।

7 दिन, 1400 किलोमीटर और 25 जांबाज राइडर- इस विशेष टूर में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों की 25 अनुभवी महिला बाइक राइडर्स शामिल हैं। यह दल 7 से 13 मार्च तक मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू होगा। मुख्यमंत्री ने राइडर्स से संवाद करते हुए कहा कि यह यात्रा मध्यप्रदेश की बेटियों के लिए अद्वितीय और साहसपूर्ण सिद्ध होगी। देश सुरक्षित है और मध्यप्रदेश भी सुरक्षित है। हमारी ये बहनें मध्यप्रदेश में महिला सुरक्षा की गारंटी के रूप में इस टूर पर निकल रही हैं। निमाड़ की सादगी से लेकर चंबल के गौरवशाली इतिहास तक, वे हमारे प्रदेश की विविधता को दुनिया के सामने रखेंगी।

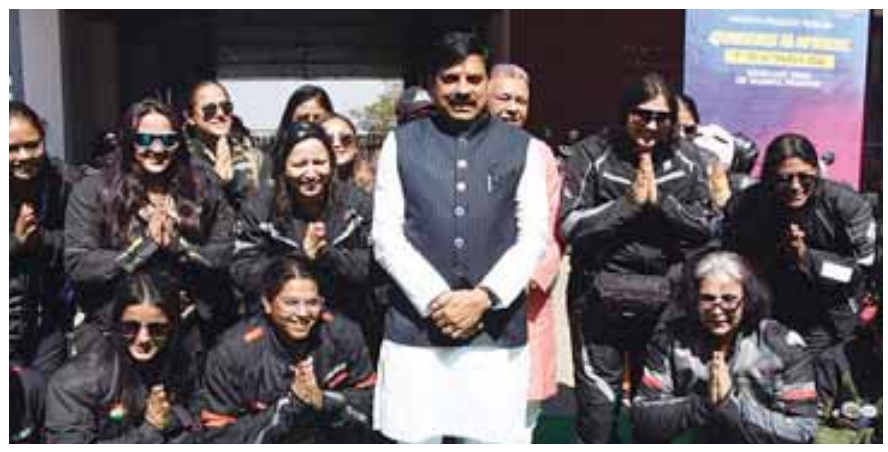

सुरक्षा और संवाद पर जोर

मुख्यमंत्री ने दल में शामिल राइडर्स को एक्सपर्ट बताते हुए उन्हें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। साथ ही, जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि इन महिला राइडर्स के ठहरने और भोजन की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम में पर्यटन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से भी मुख्यमंत्री ने संवाद किया, जो इस पूरी यात्रा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रचारित करेंगे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे।

चीन के बाद होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों की भी आवाजाही शुरू

- हो गया है सीक्रेट समझौता! आईआरजी ने अमरीका को दी चेतावनी

तेहरान (एजेंसी)। चीन के बाद भारतीय कार्गो जहाज भी होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने लगे हैं। ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि भारत के दो कार्गो जहाज पुष्पक और अब परिमल इस व्यापारिक मार्ग से पूरी रफ्तार के साथ गुजर रहे हैं। इससे पहले ईरान ने सिर्फ चीन के कार्गो जहाजों को ही इस रास्ते से गुजरने की मंजूरी दी थी लेकिन अब जबकि दो भारतीय जहाज इस रास्ते में हैं तो ऐसा लग रहा है कि भारत और ईरान के बीच कोई समझौता हो गया है या फिर ये दोनों जहाज अपने रिस्क पर इस रास्ते से गुजर रहे हैं।

- **भारत और ईरान के बीच गुपचुप समझौता हुआ!-** भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों की उस वक्त बात हुई है जब अमेरिका ने श्रीलंका के पास डेना नाम के युद्धपोत पर हमला कर उसे डुबो दिया। ये जहाज भारतीय नौसेना के साथ एक युद्धाभ्यास के बाद लौट रहा था। इसे ईरान के समुद्र तट से करीब 2,000 मील दूर इंटरनेशनल पानी में बिना किसी पहले चेतावनी के निशाना बनाया गया था। इस हमले के बाद भारत ने हिंद महासाग में फंसे दूसरे जहाजों को शरण देना शुरू कर दिया है। द हिंदू ने दावा किया कि भारत ने एक ईरानी जहाज को कोच्चि में डॉक करने की इजाजत दी है।

आईआरजी ने कहा-कर रहे हैं अमेरिका का इंतजार

होर्मुज स्ट्रेट से उस वक्त भारतीय कार्गो जहाज गुजर रहे हैं जब ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि वे यूएस सेना के होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को एस्कॉर्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो इस व्यापारिक मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी को लेकर आईआरजी ने ये नई चेतावनी जारी की है। समाचार एजेंसीकी रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारी सलाह है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अमेरिकी 1987 में अमेरिकी सुपरटैंकर ब्रिजटन में लगी आग को याद करें। दूसरी तरफ पहले पुष्पक और अब परिमल को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते देखा जा रहा है। इस व्यापारिक मार्ग को फिलहाल 'मौत का मुंह' कहा जा रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि या तो ईरान के साथ भारत का कोई सीक्रेट समझौता हो गया है या फिर इन दोनों जहाजों ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही इन समुद्री रास्तों में जहाजों पर हमले कर रहे हैं ऐसे में हो सकता है कि ईरान ने भारत की मदद की हो।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 25 °c

न्यूनतम 22°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ रविवार, 08 मार्च 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संत राम रहीम पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में बरी

- हाईकोर्ट ने दिया फैसला,7 साल पहले उम्रकैद हुई थी, 3 अन्य की सजा बरकरार

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को बरी कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने 3 आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की सजा को बरकरार रखा है। इससे पहले 17

जनवरी 2019 को पंचकूला की स्पेशल कोर्ट ने राम रहीम समेत बाकी सभी आरोपियों को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस हत्याकांड में राम रहीम के साजिशकर्ता होने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं। जिस वजह से राम रहीम को बरी कर दिया गया। राम रहीम इससे पहले डेरा मैनेजर रणजीत हत्याकांड में पहले ही हाईकोर्ट से बरी हो चुका है। हालांकि सीबीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राम रहीम को साध्वियों के यौन शोषण केस में 10 साल कैद की सजा हुई है।

'यात्रा' से पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करेंगे निशांत

- पिता नीतिश की तरह ही बनाया प्लान, ब्लू प्रिंट भी तैयार

पटना (एजेंसी)। सीएम नीतिश कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को जेडीयू विधानमंडल दल की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे। इस बैठक में तय हो गाया कि निशांत कुमार 8 मार्च को जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। निशांत कुमार इसके बाद बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। कुल मिलाकर इन सब बातों का निचोड़ अब साफ दिखने लगा है। निशांत कुमार पिता नीतिश कुमार की तरह ही अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करेंगे। याद कीजिए

2005 के फरवरी में हुए चुनावों को जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। सत्ता की चाबी लोजपा के पास थी लेकिन दिवंगत रामविलास पासवान किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अड़ गए थे। तब नीतिश कुमार ने क्या किया था। पिता नीतिश कुमार की तरह ही निशांत कुमार भी यात्रा से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जनता और कार्यकर्ता का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी यात्रा का नाम आशीर्वाद यात्रा भी रखा जा सकता है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि निशांत कुमार की यात्रा का नाम क्या होगा।

दुर्भाग्य है कि धर्मयुद्ध के लिए निकलना पड़ रहा

- शंकराचार्य बोले-जिंदा हिंदू लखनऊ चलें लिखे पोस्टर बांटे

वाराणसी (एजेंसी)। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा है। अपने ही देश में, अपने ही वोट से चुनी सरकार के सामने, अपनी ही गौ-माता को बचाने के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये बातें काशी में लखनऊ रवाना होने से पहले शनिवार को कही। शंकराचार्य ने इस आंदोलन को गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध सभा का नाम दिया। वह 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे। यहां हजारों संतों

की मौजूदगी में सभा करेंगे। इसमें सरकार से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग करेंगे। शंकराचार्य ने 30 जनवरी को योगी सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने तब कहा था- गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें। वरना आंदोलन करेंगे। शंकराचार्य काशी से जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर होते हुए 5 दिन बाद लखनऊ पहुंचेंगे। यात्रा में 20 से अधिक गाड़ियां हैं। 500 से अधिक श्रद्धालु साथ हैं। इस दौरान लोगों को पोस्टर बांटे गए। इनमें लिखा है- जिंदा हिंदू लखनऊ चलें। इससे पहले, शंकराचार्य सुबह 8.30 बजे मठ से निकलकर गौशाला पहुंचे। गाय की पूजा की। फिर पालकी पर सवार हुए।

इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड परियोजना किसान और सरकार के बीच विश्वास की बनेगी मिसाल: सीएम

3 हजार करोड़ की लागत के बनेगा मार्ग

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड के किसानों के हित में जमीनी स्तर पर मार्ग निर्माण को स्वीकृति और उचित मुआवजे की व्यवस्था किए जाने पर इंदौर जिले के सांवेर क्षेत्र के निवासियों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पगड़ी और बड़ी माला पहनाकर उनका अभिवादन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास पधारे सभी लोगों को होली और रंगपचमी की बधाई दी। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 3 हजार करोड़ रुपए की लागत से इंदौर और उज्जैन के बीच बनने वाली सड़क से इंदौर और उज्जैन का सफर सवा घंटे की जगह आधे घंटे का रह जायेगा। दोनों शहरों के बीच तेज कनेक्टिविटी से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। स्थानीय स्तर पर उद्योग, लॉजिस्टिक पार्क, किसानों को मण्डियों तक पहुंच और व्यापारियों तथा उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह मार्ग, देश के व्यापार व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रो के बीच इस मार्ग से यात्रा सुगम और कम समय में होगी। परिणामस्वरूप आवागमन बढ़ेगा और देश में इंदौर-उज्जैन क्षेत्र का महत्व और अधिक बढ़ेगा।

इंदौर-उज्जैन क्षेत्र में विकास के नए युग का होगा सूत्रपात

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पारम्परिक और ऐतिहासिक रूप से इंदौर और उज्जैन के बीच इस मार्ग का ही उचित उपयोग होता था। इस मार्ग से इंदौर के 20 और उज्जैन के 6 गांव लाभान्वित होंगे। सिंहस्थ के लिए भी यह मार्ग सुविधाजनक और उपयोगी होगा। इंदौर-उज्जैन क्षेत्र में विकास की दृष्टि से नए युग का सूत्रपात हो रहा है। राज्य सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है।

किसानों के हर खेत तक पहुंचेगा सिंचाई के लिये पानी : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। प्रत्येक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। केन-बेतना नदी जोड़ो परियोजना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) परियोजना सहित आधुनिक सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई का रकबा तेजी से बढ़ रहा है। गत 2 वर्ष में ही प्रदेश में सिंचाई का रकबा 10 लाख हैक्टेयर बढ़ा है। अब प्रदेश की 55 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश नदियों का मायका है। हम अपनी नदियों से राजस्थान और उत्तरप्रदेश को भी पानी उपलब्ध कराते हैं। बिहार और गुजरात को भी पानी मिलता है। पूर्व सरकारों ने नदियों की जलराशि का उचित प्रबंधन करने पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हमारी सरकार के प्रयासों से विदिशा जिले को भी केन-बेतवा नदी परियोजना का पूरा लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश आज बिजली सरप्लस स्टेट है। अब किसानों को दिन में भी सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। हमारे लिए खेतों में किसान और सीमा पर जवान दोनों बराबर है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं और अंदरूनी इलाके सुरक्षित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने विदिशा में प्रदेश की पहली जिला स्तरीय फिंगर प्रिंट लैब का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को शमशाबाद में कृषक हितग्राही सम्मेलन और विकास कार्यों के भूमि-पूजन एवं लोकर्पण कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों को हर साल 12 हजार रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में दिए जा रहे हैं। विदिशा जिला कृषि उत्पादन के मामले में अग्रणी है।

पड़ोसी देशों पर अब कोई हमले नहीं करेगा ईरान

राष्ट्रपति पेजेशकियन ने किया वादा, मांगी भी माफी

तेहरान (एजेंसी)। ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन ने कहा कि सैन्य बलों को एक आदेश दिया गया है। अब से, पड़ोसी देशों पर तब तक हमला न करें जब तक कि उन पर पहले हमला न हो। जो लोग इस मौके का फायदा उठाकर ईरान पर हमला करने की सोच रहे हैं, उन्हें साम्राज्यवाद की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने पड़ोसी देशों से माफी मांगते हुए कहा है कि अब ईरान उन देशों पर हमला नहीं करेगा। पेजेशकियान ने ईरान के सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक वीडियो संदेश में कहा,मुझे लगता है कि उन पड़ोसी देशों से माफी मांगना जरूरी है जिन पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा, हमारा पड़ोसी देशों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। हम शांति और सुकून कायम करने के लिए इलाके में सहयोग की अपील करते हैं। पेजेशकियन ने कहा, सैन्य बलों को एक आदेश दिया गया है। अब से, पड़ोसी देशों पर तब तक हमला न करें जब तक कि उन पर पहले हमला न हो।

- **सऊदी अरब ने दी थी ईरान को चेतावनी-** इससे पहले, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने देश के सैन्य ठिकानों और तेल केंद्रों पर हुए सिलसिलेवार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद ईरान को गलतफहमी और गलत आंकलन से बचने की कड़ी चेतावनी दी थी। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बयान जारी कर बताया कि अमेरिकी सैन्य कर्मियों की मौजूदगी वाले एक एयर बेस और एक प्रमुख तेल क्षेत्र को निशाना बनाकर किये गये हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, राजधानी रियाद के दक्षिण-पूर्व स्थित प्रिंस सुल्तान एयर बेस की ओर दागी गयी एक बैलिस्टिक मिसाइल को बीच में ही रोककर नष्ट कर दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी ने मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से पुष्टि की है कि इसी एयर बेस पर एक और मिसाइल हमला हुआ, जिसे भी विफल कर दिया गया।

संकट में भारत को मिला ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का साथ

भारत में अतिरिक्त गैस सप्लाई के लिए बढ़ा दिया अपना हाथ

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इससे भारत समेत कई देशों को क्रूड ऑयल और गैस की दिक्कत हो सकती है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत कई देशों ने भारत को अतिरिक्त गैस सप्लाई की पेशकश की है। सूत्रों ने कहा मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति अब किसी एक समुद्री मार्ग पर निर्भर नहीं है। एक ही समुद्री मार्ग पर निर्भरता के दिन अब लद चुके हैं। भारत जितना तेल आयात करता है, उसका करीब आधा हिस्सा हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। बाकी का क्रूड ऑयल अन्य मार्गों से आता है, जो अभी प्रभावित नहीं हैं।

अमेरिका और यूएई के साथ नए समझौते

भारत ने हाल ही में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे साझेदार देशों के साथ भी नई ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थाएं की हैं। इसका मकसद है कि लंबी अवधि के लिए स्थिर सप्लाई सुनिश्चित हो सके। पिछले दस वर्षों में भारत ने अपनी तेल आपूर्ति के स्रोत 27 देशों से बढ़ाकर 40 देशों तक कर दिए हैं, जो छह महाद्वीपों में फैले हुए हैं। वैश्विक संकट के कारण पिछले कुछ दिनों में क्रूड ऑयल की कीमत करीब 15 फीसदी बढ़ गई है। इसके बावजूद भारत में ईंधन कीमतों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है। पाकिस्तान में पेट्रोल कीमतें लगभग 55 फीसदी बढ़ गई हैं। वहीं जर्मनी में 22,फ्रांस में 19 फीसदी और अमेरिका में 11 फीसदी से ज्यादा उछाल आया है।

अब भारत बनेगा राफेल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब

फ्रांस के बाहर बड़ी उपलब्धि, डसॉल्ट ने बताया प्लान

पेरिस (एजेंसी)। राफेल फाइटर जेट बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने पुष्टि कर दी है कि फ्रांस के बाहर प्रोडक्शन लाइन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा डसॉल्ट ने कहा है कि राफेल फाइटर की प्रोडक्शन क्षमता को भी साल 2029 तक हर महीने बढाकर 4 करने का लक्ष्य रखा गया है। डसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने 4 मार्च को कहा है कि वह धीरे-धीरे राफेल फाइटर का प्रोडक्शन रेट बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि 2029 तक हर महीने चार राफेल बनाने का लक्ष्य है लेकिन उसे बढ़ाकर पांच करने पर भी विचार चल रहा है। पिछले कुछ सालों में यह बढ़ोतरी एक्सपोर्ट सेल्स को सपोर्ट कर रही है, और कंपनी को और ऑर्डर पूरे करने के लिए तैयार कर रही है। इस बीच, डसॉल्ट देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में फाइटर की बड़ी सब-असेंबली बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चूंकि एयरफ्रेमर दक्षिण एशियाई देश के साथ एक और बड़े कॉन्ट्रैक्ट की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए वह और भी ज्यादा लोकल प्रोडक्शन के लिए तैयारी कर रहा है।

लोग केरल स्टोरी-2 नहीं देख रहे, ये अच्छी खबर

राहुल बोले-फिल्मों और मीडिया का इस्तेमाल प्रोपेगैंडा के लिए हो रहा

इडुक्की (एजेंसी)। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि फिल्म केरल स्टोरी-2 गोज बियॉन्ड को ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं और यह अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि फिल्मों, टीवी और मीडिया का इस्तेमाल तेजी से प्रोपेगैंडा के रूप में किया जा रहा है। केरल में इडुक्की के कुट्टिकनम स्थित मैरियन कॉलेज में शुक्रवार को छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की। एक छात्र ने फिल्मों के प्रोपेगैंडा के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर

सवाल पूछा था। इस पर गांधी ने कहा- अच्छी खबर यह है कि केरल स्टोरी खोखली लगती है और लोग इसे देखने नहीं जा रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि बहुत से लोग केरल और उसकी परंपराओं व संस्कृति को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने कहा कि आज फिल्मों, टेलीविजन और मीडिया को तेजी से नफरत फैलाने का हथियार बनाया जा रहा है। इनका इस्तेमाल लोगों को बदनाम करने, उन्हें खत्म करने और समाज में फूट डालने के लिए किया जाता है, ताकि कुछ लोगों को फायदा हो और दूसरों को नुकसान हो। **यूनिवर्सिटी में आरएसएस से जुड़े लोग-** देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक खास विचारधारा का दबाव बढ़ रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर देखें तो उनमें से कई की नियुक्ति इसलिए हुई है क्योंकि वे आरएसएस या किसी खास विचारधारा से जुड़े हैं। शिक्षा को किसी एक सोच तक सीमित नहीं होना चाहिए। भारत अभी अमेरिका और चीन के स्तर तक नहीं पहुंचा है। यदि भारत एआई के क्षेत्र में मजबूत बनना चाहता है, तो उसे अपने डेटा पर नियंत्रण रखना होगा। अमेरिका को वैश्विक डेटा तक व्यापक पहुंच है, जबकि चीन अपना डेटा खुद नियंत्रित करता है, जिससे एआई में उसकी स्थिति मजबूत होती है। ऊपर से देखने पर वेस्ट एशिया में चल रहा तनाव अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान का संघर्ष लगता है, लेकिन बड़े जियोपॉलिटिकल खिलाड़ी उलझेंगे।

राज्यसभा चुनाव में विपक्ष का समीकरण बिगाड़ेगी भाजपा

- बनाया बड़ा प्लान, कांग्रेस को फिर लग सकता है तगड़ा झटका

नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्यसभा की दस राज्यों की 37 सीटों में केवल तीन राज्यों की 11 सीटों के लिए ही मतदान होगा। इनमें बिहार की पांच, ओडिशा की चार एवं हरियाणा की दो सीट शामिल हैं। अन्य राज्यों में निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय है। इस बीच भाजपा ने ओडिशा में बीजू जनता दल और हरियाणा में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं, बिहार में राजद और एनडीए में एक सीट के लिए कड़ा मुकाबला हो सकता है। ओडिशा में भाजपा दो और बीजद एक सीट जीत सकती है, लेकिन चौथी सीट पर भाजपा समर्थित निर्दलीय दिलीप राय और बीजद के दत्तेश्वर होता में सीधा मुकाबला है। जीत के लिए 30 वोट चाहिए। भाजपा के पास अपने 79 और तीन निर्दलीय का समर्थन है। यानी तीसरे प्रत्याशी के लिए 22 वोट बचे हैं। ऐसे में दिलीप रे के लिए आठ वोट और चाहिए। वहीं बीजद के 48 विधायक हैं उसे दूसरी सीट के लिए 12 वोट चाहिए।

भारत में छात्रों का 'लोन वुल्फ' नेटवर्क बनाने का प्लान

देश में जैश-ए-मोहम्मद की साजिश का हो गया भंडाफोड़

नई दिल्ली (एजेंसी)। जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन ने एक मेडिकल संस्थान में घुसपैठ कर डॉक्टरों को भारत में हमले करने के लिए अपने साथ जोड़ लिया था। जांच एजेंसियों के अनुसार इस व्हाइट-कॉलर मॉड्यूल ने करीब 2500 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जुटा लिया था और दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई हमले करने की योजना बनाई थी। खुफिया एजेंसियों को अब एक और साजिश का पता चला है, जिसमें जैश ए मोहम्मद स्कूलों और कॉलेजों में घुसपैठ कर छात्रों को कट्टरपंथ की ओर मोड़ने की योजना बना रहा था। आतंकी संगठन अपने प्रचार सामग्री के जरिए कुछ छात्रों को भर्ती करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वे अपने दोस्तों के बीच भी उसकी

विचारधारा फैलाएं। एक अधिकारी ने बताया कि छात्रों को शामिल करने की यह रणनीति दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। ऐसी रणनीति पहले जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा की ओर से पाकिस्तान में अपनाई जा चुकी है और अब इसे भारत में लागू करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, कम उम्र में छात्रों को कट्टरपंथ की ओर मोड़ने से इन संगठनों को लंबे समय में फायदा होता है। जब ये छात्र 20-25 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो वे इतने कट्टर बन चुके होते हैं कि देशभर में हमले करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बीच महाराष्ट्र एटीएस ने इस सप्ताह मुंबई से एक छात्र को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान अयान शेख के रूप में हुई है।

धीरे-धीरे युवाओं को जोड़ रहा था ये संगठन

अधिकारियों के अनुसार संगठन जल्दबाजी में बड़ी संख्या में भर्ती नहीं करना चाहता, बल्कि अगले 5 से 10 वर्षों की योजना बनाकर धीरे-धीरे युवाओं को जोड़ रहा है, ताकि समय-समय पर हमले करने के लिए उसके पास पर्याप्त लोग मौजूद रहें। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस योजना में बड़े मॉड्यूल बनाने के बजाय 'लोन वुल्फ' या दो लोगों की छोटी टीम पर जोर दिया जा रहा है।

फरीदाबाद मॉड्यूल से साजिश का खुलासा

फरीदाबाद मामले से संगठन ने यह सीखा कि बड़े मॉड्यूल में ज्यादा लोगों के शामिल होने से संचार ट्रैक होने का खतरा बढ़ जाता है और मॉड्यूल का पर्दाफाश हो सकता है। इसलिए छात्र मॉड्यूल में हमलावरों को अकेले या 'बडी पेयर' के रूप में काम करने के लिए तैयार किया जाएगा।

रंगपंचमी गेर पर ड्रोन और सीसीटीवी से रहेगी नजर, डीजे और मास्क बंद रहेगा

प्रशासन की गेर की तैयारियां पूरी, हुड़दंगियों-नशाखोरों पर कार्रवाई

इंदौर। शहर में रविवार को रंग पंचमी का पर्व पारंपरिक तरीके से उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहर के निर्धारित मार्गों से विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा रंगारंग गेर निकलेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि गेर के दौरान किसी भी प्रकार की हुड़दंग या अव्यवस्था करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन और सीसीटीवी से गेर पर नजर रखी जाएगी, डीजे और मास्क पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। गेर आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा की विशेष उपस्थिति में नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल, डीसीपी आनंद कलादगी, एडीएम रोशन राय सहित जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आयोजकों के साथ गेर की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक में बताया गया कि गेर की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और यह शहर के पारंपरिक मार्गों से ही निकाली जाएगी। राधा-कृष्ण फाग यात्रा के साथ टोरी कॉर्नर, मॉरल क्लब और संगम कॉर्नर सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा गेर निकाली जाएगी। आयोजकों ने कार्यक्रम से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रशासन को दी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि सभी गेर निर्धारित समय और तय क्रम के अनुसार ही निकाली जाएं तथा अनुशासन और शालीनता का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में निर्देश दिए गए कि गेर में केवल अनुमति प्राप्त वाहन ही शामिल किए जाएं। वाहनों के चालक लाइसेंसधारी हों और किसी भी प्रकार के नशे की हालत में न हों। साथ ही वाहनों की फिटनेस की भी जांच सुनिश्चित की जाएगी।

ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी- डीसीपी आनंद कलादगी ने बताया कि गेर के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। पूरे मार्ग को विभिन्न सेक्टरों में बांटकर निगरानी रखी जाएगी और सेक्टरवार कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। ड्रोन, सीसीटीवी और वीडियो कैमरों के माध्यम से लगातार नजर रखी जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि यदि गेर के दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि या हथियार रखने वाला व्यक्ति दिखाई दे, तो इसकी तत्काल सूचना पुलिस को दें। आयोजन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए वालंटियर की संख्या बढ़ाने तथा महिला वालंटियर भी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी वालंटियर को पहचान पत्र भी दिए जाएंगे।

फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस रहेंगी – किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। प्रशासन और आयोजकों ने संयुक्त रूप से प्रयास कर इंदौर की इस ऐतिहासिक परंपरा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने का संकल्प लिया है।

बसों-लोडिंग वाहन प्रतिबंधित – जवाहर मार्ग, राजवाड़ा क्षेत्र में सिटी बस एवं अन्य लोडिंग वाहन नहीं जाएंगे। सिटी बस, दोपहिया, चार पहिया वाहन मृगनयनी, सुभाष मार्ग, गंगवाल बस स्टैंड, महूनाका, पलसीकर चौराहा, टावर चौराहा, भवरकुआं से आ-जा सकेंगे। यह प्रतिबंध रीगल चौराहा, पटेल प्रतिमा, कलेक्ट्रेट, महूनाका, शिवानी होटल तिराहा, वायरलेस चौराहा से लागू होगा। जबकि,संजय सेतु से राजमोहल्ला, नगर निगम से बड़ा गणपति, हरसिध्दि से यशवंत रोड, नयापीठा से नरसिंह बाजार की ओर चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

ये रहेगा परिवर्तित मार्ग- गेर मार्ग बड़ा गणपति से कृष्णपुरा छत्री, नंदलालपुरा से राजमोहल्ला एवं राजवाड़ा के आसपास पीपली बाजार, सराफा, बर्तन बाजार, इमामबाडा, कपडा मार्केट में वाहनों का आवागमन एवं पार्किंग नहीं होगा। जो वाहन मृगनयनी चौराहा से राजमोहल्ला कलेक्ट्रेट की ओर जाना चाहते है. वे संजय सेतु से होकर जा सकेंगे। जो वाहन हरसिध्दी से मच्छी बाजार जवाहर मार्ग में आगे की ओर जाना चाहते है. वे मच्छी बाजार चौराहे से गंगवाल बस स्टैंड चौराहा से आगे की ओर जा सकेंगे। जो वाहन नरसिंह बाजार से होकर मरीमाता चौराहा जाना चाहते हैं, वे वाहन गंगवाल चौराहा, अंतिम चौक, बडा गणपति सुभाष मार्ग होकर आगे की ओर आ-जा सकेंगे। ऐसे वाहन जो इमली बाजार, रामबाग चौराहा से राजबाड़ा की ओर आना चाहते हैं। ऐसे वाहन चालक सुभाष मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। सिटी बसों का आवागमन संजय सेतु से राजमोहल्ला तक प्रतिबंधित रहेगा। वे संजय सेतु से मृगनयनी से नगर निगम, लोखंडे, मरीमाता चौराहा होकर एयरपोर्ट, गंगवाल तथा भंवरकुआं की ओर जा सकेंगे।

यह मार्ग प्रतिबंधित रहेगा

हेमिल्टन रोड एवं फ्रूट मार्केट से राजवाड़ा, संजयसेतु से मृगनयनी और नंदलालपुरा, इमली बाजार से राजवाड़ा, बड़वाली चौकी से गोराकुंड, यशवंत रोड चौराहे से राजवाड़ा, मच्छी बाजार से यशवंत रोड चौराहा, रामलक्ष्मण बाजार से पीपली बाजार, नृसिंह बाजार से शीतलामाता बाजार, नयापीठा चौराहा से नरसिंह बाजार, जयरामपुरा तिराहे से नयापीठा चौराहा, बियाबानी चौराहे से दरगाह तिराहा, बियाबानी चौराहे से मालगंज चौराहा, मालगंज चौराहा से लोहार पट्टी, इतवारिया चौराहा से जी. सच्चिदानंद चौराहा, अंतिम चौराहा से लोहार पट्टी, जवाहर मार्ग, सराफा थाना, बजाज खाना चौक से सराफा थाना, बर्तन बाजार गली से विजय जाट हाउस, निहालपुरा गलियों में वाहन नहीं जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री की गाड़ी को युवक ने रोका मां की मौत पर उनसे न्याय की मांग

इलाज में लापरवाही का आरोप, मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर सवाल

इंदौर। शुक्रवार को उस समय अचानक हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के काफिले के सामने एक युवक आ गया और अपनी मां की मौत के मामले में न्याय की मांग की। उसने मुख्यमंत्री की गाड़ी के सामने खड़े होकर अपनी पीड़ा बताई। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया, वहीं मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मुद्दा उठा। युवक रोहन चौहान अपनी मां मंजू चौहान की मौत को लेकर लंबे समय से कार्रवाई की मांग कर रहा है। रोहन का आरोप है कि करीब पांच महीने पहले उसकी मां को सर्दी-खांसी की शिकायत थी, जिसके चलते उन्हें एक निजी क्लिनिक में इलाज के लिए ले जाया गया था। वहां एक बीएचएमएस डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन और बॉटल लगाई, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और कुछ ही समय में उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि यह स्पष्ट रूप से चिकित्सा लापरवाही का मामला है। रोहन का आरोप है कि उसने कई बार संबंधित विभागों और अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी नाराजगी और बेबसी के चलते उसने मुख्यमंत्री के काफिले को रोककर सीधे उनसे न्याय की गुहार लगाई। घटना के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत युवक को काबू में लिया, जबकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उसे शांत रहने को कहा और मामले में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भी जांच करवाने की बात कही।

महिला मौत का मामला

जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में इलाज के दौरान महिला की मौत के मामले में पुलिस पहले ही क्लिनिक संचालक और डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने बिजलपुर के मार्तंड नगर निवासी रोहन चौहान की शिकायत पर हर्ष क्लिनिक, खातीवाला टैंक के संचालक श्रीचंद पिता साबूमल बागेजा और डॉक्टर ज्ञान एस पंजवानी के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि हर्ष क्लिनिक में फर्जी डिग्री के आधार पर इलाज किया जा रहा था और प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग किया जा रहा था। मामले में कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील भी किया गया था। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन पर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया।

23 अमानक संस्थानों पर 51 लाख का जुर्माना

इंदौर। अमानक खाद्य सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। विभिन्न जांच में खाद्य पदार्थों के नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर कुल 23 अलग-अलग संस्थानों पर लगभग 51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। अपर कलेक्टर पवार नवजीवन विजय की न्यायालय में विधिवत सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान घी, पनीर सहित अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाए गए थे, जिसके आधार पर संबंधित संस्थानों पर दंड लगाया गया। कार्रवाई में अपकिन एग्रो पर सबसे अधिक 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि मशाल होटल सहित अन्य प्रतिष्ठान भी इस कार्रवाई की जद में आए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर अलग-अलग संस्थानों पर 30 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है।

पति को लेकर दो बीबियां भिड़ी, केस दर्ज

इंदौर। चंदन नगर थाना क्षेत्र में पति को लेकर दो महिलाओं के बीच विवाद का मामला सामने आया है। झगड़ा बढ़ने पर दोनों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला घायल हो गई। पुलिस को गीता नगर निवासी ताहेरा शाह ने बताया कि मैं अपने पति वारिस अली के साथ घर पर थी। इसी दौरान वारिस अली की दूसरी पत्नी साइना बी वहां पहुंच गई। मेरे घर आने को लेकर जब मैंने उससे बात की तो वह बहस करने लगी, जो कुछ ही देर में तीखी नोकझोंक में बदल गई। बताया जा रहा है कि ताहेरा ने साइना को शांत रहने और समझाने की कोशिश की, लेकिन वह भड़क गई। आरोप है कि इसके बाद साइना ने ताहेरा के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट कर पेट में लात मार दी। घटना के दौरान घर में मौजूद वारिस अली और रिश्तेदार ने बीचबचाव कर मामला शांत कराया। मारपीट में घायल ताहेरा को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया। बाद में हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे एमवाय अस्पताल रैफर कर दिया। अस्पताल में पुलिस ने घायल महिला के बयान दर्ज किए हैं।

टावर तोड़ते समय गिरे मजदूर की मौत

इंदौर। विजयनगर थाना क्षेत्र में निर्माण कार्य के दौरान हुए हादसे में मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय हरिओम सिंह निवासी कुलकर्णी का भट्टा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, 28 फरवरी को हरिओम सिंह मकान की तीसरी मंजिल पर बने टॉवर को तोड़ने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक छत का एक हिस्सा भरभराकर उनके ऊपर गिर गया, जिससे वे मलबे में दब गए। साथियों ने उन्हें बाहर निकालकर ठेकेदार महेश की मदद से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतक के परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि काम के दौरान मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर ठेकेदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। हरिओम सिंह के परिवार में पत्नी और एक बेटा है।

2 लाख की चोरी, कैमरे में कैद बदमाश

इंदौर। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के लोहामंडी इलाके में अज्ञात बदमाशों ने बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात ऑफिस का ताला तोड़कर 2 लाख रुपए चुरा लिए। घटना की जानकारी गुरुवार सुबह तब लगी, जब ऑफिस के रहने वाले युवक ने शटर का ताला टूटा होने की फरियादी को सूचना दी। फरियादी सुनील कुमार राजचंदानी निवासी संजना पार्क में अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पास ने बताया कि उनका ऑफिस मनवानी कॉम्प्लेक्स में मालवा ट्रांसपोर्ट के सामने लोहामंडी में है। 5 मार्च की सुबह ऑफिस के सामने रहने वाले दिलीप ने उन्हें चोरी होने की जानकारी दी थी। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और ऑफिस जाकर देखा तो टेबल में रखी अलमारी से 2 लाख रुपए गायब थे। बाद में जब ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई तो देर रात दो बदमाश ताला तोड़ते हुए नजर आए। चोरी की पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने और उनकी तलाश में जुटी हुई है।

कुख्यात बदमाश सादिक काला की गुंडागर्दी निकाली, जुलूस निकला

घर में घुसकर चाकू की नोक पर वसूली करने वाला गिरफ्तार

इंदौर। चंदन नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कुख्यात बदमाश सादिक काला पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी हेकड़ी निकाल दी। साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर चाकू की नोक पर वसूली करने वाले इस आरोपी को पुलिस ने कुछ ही घंटों में दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका जुलूस उसी इलाके में निकाला, जहां उसका खौफ बताया जाता था, ताकि लोगों के मन से डर खत्म किया जा सके। पुलिस के अनुसार फरियादी नसीम बी और सिद्दीक पठान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सादिक काला, अज्जू बटला और फैयाज उनके घर में घुस आए और मारपीट करते हुए चाकू दिखाकर अवैध रुपयों की मांग करने लगे। शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी तिलक करोले के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सादिक काला के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया प्रतिबंधित खटकेदार चाकू भी बरामद हुआ।

सार्वजनिक रूप से मांगी माफी

पुलिस ने बदमाश का रानी पैलेस सहित उसके प्रभाव वाले क्षेत्रों में जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी सड़क पर घुटनों के बल बैठकर कान पकड़कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगता नजर आया और भविष्य में अपराध नहीं करने की कसम खाई। पुलिस के अनुसार सादिक काला पर हत्या, हत्या के प्रयास और वसूली सहित करीब 14 गंभीर अपराध दर्ज हैं। थाना प्रभारी तिलक करोले ने नागरिकों से अपील की कि वे ऐसे बदमाशों से न डरें और किसी भी घटना की तुरंत पुलिस को सूचना दें।

महू नाका चौराहे पर ट्रैफिक चालान से बढ़ी परेशानी, व्यवस्था बिगड़ी

पार्किंग स्थल पर कार्रवाई से व्यापारियों में रोष, ग्राहकों को भी दिक्कत

इंदौर। व्यस्त महू नाका चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की लगातार चालानी कार्रवाई अब स्थानीय व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। महू नाका नगर निगम मार्केट के व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस अब चौराहे के बजाय सीधे मार्केट के पास बने पार्किंग स्थलों पर वाहनों को रोककर चालान कर रही है। इससे बाजार क्षेत्र में अव्यवस्था की स्थिति बन रही है और ग्राहकों व व्यापारियों दोनों को वाहन खड़े करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी सुमित तिवारी ने बताया कि पहले ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करती थी, लेकिन अब मार्केट के पास बने पार्किंग स्थल पर ही वाहनों को रोककर चालान किया जा रहा है। इससे वहां वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और बाजार की सामान्य गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं।

ग्राहकों के आने में हो रही कमी

व्यापारियों का कहना है कि उनकी दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को वाहन खड़े करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा है। पार्किंग में कार्रवाई के डर से कई ग्राहक बाजार आने से बचने लगे हैं, जिससे व्यापार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस से मांग की है कि मार्केट क्षेत्र में व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि व्यापारियों और ग्राहकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और बाजार की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सकें।

शराब दुकानों के आवंटन की बैच-2 ई-टेंडर प्रक्रिया जारी

इस बार 121.08 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई

इंदौर। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शराब दुकानों के आवंटन की ई-टेंडर एवं ई-टेंडर-कम-ऑक्शन प्रक्रिया जारी है। इसके पहले चरण के बैच-1 और बैच-2 की कार्रवाई प्रगति पर है। 2 मार्च को पहले चरण के बैच-1 के अंतर्गत 19 समूहों में से 11 समूहों के लिए ई-टेंडर और नीलामी पूरी की गई। 11 समूहों का कुल आरक्षित मूल्य 452.74 करोड़ रुपए निर्धारित किया था, जबकि नीलामी में 498.37 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली मिली हुई। यह आरक्षित मूल्य से 10.08 प्रतिशत अधिक है। वहीं पिछले वर्ष के वार्षिक मूल्य 377.28 करोड़ रुपए की तुलना में इस बार 121.08 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो 32.09 प्रतिशत अधिक है। 5 मार्च को पहले चरण के बैच-2 के अंतर्गत 12 समूहों की प्रक्रिया पूरी की गई। इन समूहों का पिछले वर्ष का वार्षिक आधार मूल्य 325.86 करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2026-27 के लिए आरक्षित मूल्य 391.03 करोड़ रुपए तय किया गया था। इन समूहों के लिए 448.20 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली मिली, जो पिछले वर्ष के मूल्य से 37.54 प्रतिशत और आरक्षित मूल्य से 14.62 प्रतिशत अधिक है।

23 समूहों की प्रक्रिया पूरी

6 मार्च तक की स्थिति के अनुसार, पहले चरण के बैच-1 और बैच-2 के 38 समूहों में से 23 समूहों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन समूहों का पिछले वर्ष का कुल वार्षिक आधार मूल्य 703.15 करोड़ रुपए था, जबकि 2026-27 के लिए 843.78 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। इन समूहों के लिए 946.58 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली आई। यह राशि पिछले वर्ष के वार्षिक मूल्य से 34.62 प्रतिशत और आरक्षित मूल्य से 12.18 प्रतिशत अधिक है।

शादीशुदा महिला ने फांसी लगाई, पति व ससुराल वालों पर आरोप

परिवार ने कहा, बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया गया

इंदौर। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार सुबह परिवार के लोगों ने उसे कमरे में फंदे पर लटका देखा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले में मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान स्नेहा (27) पत्नी नितेश थोरात निवासी प्रजापत नगर द्वारकापुरी के रूप में हुई है। स्नेहा पीथमपुर की एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी। सुबह वह नौकरी पर जाने के लिए नहीं उठी। तब परिवार ने उसे पास के कमरे में फंदे पर लटका देखा। उसका पति पेशे से ड्राइवर है। घटना के समय सास-ससुर दूसरे कमरे में थे।

परिजनों का आरोप

स्नेहा के पिता शंकर राव ने बताया कि शुक्रवार सुबह उन्हें ससुराल पक्ष के लोगों ने फोन पर घटना की जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को ससुराल में काफी समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। पिता के मुताबिक गुरुवार रात करीब 1 बजे भी उनकी बेटी से मोबाइल पर बात हुई थी, उस दौरान उसने परेशान किए जाने की बात बताई थी। गुरुवार को करीब तीन बार बेटी से घर वालों की मोबाइल पर बात हुई थी। परिजनों का कहना है कि स्नेहा और नितेश की शादी करीब 7 साल पहले हुई थी और उनका एक बेटा भी है। सास-ससुर पति और ननद पर परिवार ने आरोप लगाए है।

मायके वालों के बयान

पुलिस को मौके से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। द्वारकापुरी पुलिस का कहना है कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। मायके पक्ष के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

महापौर ने जन सहयोग से बनी बैकलेन का अवलोकन किया

बच्चों के साथ क्रिकेट खेला, स्वच्छता पर संवाद किया

इंदौर। शुक्रवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने वार्ड 66 के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था, विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य प्रभारी अश्विनी शुक्ल, महापौर प्रतिनिधि भारत पारख,क्षेत्रीय पार्षद कंचन गिदवानी सहित नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान महापौर दुबे का बगीचा,पलसीकर कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में पहुंचे तथा सफाई व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार और लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। दुबे का बगीचा क्षेत्र में नागरिकों के सहयोग से विकसित की गई बैकलेन का महापौर ने अवलोकन किया।

यहां दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनाई गई हैं और बच्चों के लिए खेल गतिविधियों की व्यवस्था की गई है। इस दौरान महापौर ने बच्चों के साथ बैकलेन में क्रिकेट भी खेला और इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास शहर की सुंदरता और स्वच्छता को बढ़ाते हैं।

नागरिकों से किया संवाद- पलसीकर कॉलोनी स्थित गोल उद्यान में महापौर ने स्थानीय रहवासियों से चर्चा कर स्वच्छता अभियान में सहयोग की अपील की।

महिला दिवस विशेष

स्मिता कुमारी
लेखक सत्यमेव मानसिक विकास केंद्र की निदेशक हैं।

नाम में क्या रखा है: नारी के अस्तित्व का संघर्ष

जब एक पुरुष के लिए यह सामान्य नहीं है, तो एक स्त्री के लिए कैसे हो सकता है? यदि 'नाम में कुछ नहीं रखा', तो पुरुषों के नाम देने की आवश्यकता ही क्या है? और यदि कार्ड में स्थान का अभाव है, तो किसी का नाम देने के बजाय केवल 'समस्त परिवार' क्यों नहीं लिखा जाता? संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तब होती है, जब शोक संदेश (मृत्यु पत्र) में भी पुत्री का नाम नहीं होता। क्या विछोह की पीड़ा केवल बेटों को होती है? क्या माता–पिता केवल बेटों के ही गुजरते हैं, बेटियों, बहुओं या दामादों के नहीं? क्या यह व्यवहार उन्हें उनके अपने ही परिवार के बीच 'बेगाना' नहीं बना देता?

कुछ समय पहले एक डॉक्टर की शादी का कार्ड आया। उस कार्ड पर परिवार के सदस्यों की सूची में उनके पालतू कुत्ते का भी नाम था। वहीं दूसरी ओर, समाज में ऐसे निमंत्रण पत्र भी बहुतायत में देखे जाते हैं जिनमें घर की बेटी, बहन, भाभी, बुआ या चाची का नाम तक नहीं होता। समाज के अधिकतर घरों की परंपराएँ हर मोड़ पर महिलाओं के अस्तित्व को गौण करने के लिए दृढ़ता से खड़ी हैं। प्रश्न यह है कि क्या कार्ड पर भाई, चाचा या दादा का नाम न हो, तब भी उनके साथ रिश्ते सामान्य माने जाएंगे? क्या वे पुरुष उस उत्सव में शामिल होंगे, जहाँ निमंत्रण पत्र पर उनका नाम न हो?

जब एक पुरुष के लिए यह सामान्य नहीं है, तो एक स्त्री के लिए कैसे हो सकता है? यदि 'नाम में कुछ नहीं रखा', तो पुरुषों के नाम देने की आवश्यकता ही क्या है? और यदि कार्ड में स्थान का अभाव है, तो किसी का नाम देने के बजाय केवल ÷समस्त परिवार÷ क्यों नहीं लिखा जाता? संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तब होती है, जब शोक संदेश (मृत्यु पत्र) में भी पुत्री का नाम नहीं होता। क्या विछोह की पीड़ा केवल बेटों को होती है? क्या माता-पिता केवल बेटों के ही गुजरते हैं, बेटियों, बहुओं या दामादों के नहीं? क्या यह व्यवहार उन्हें उनके अपने ही परिवार के बीच 'बेगाना' नहीं बना देता?

एक तरफ समाज में बेटा-बेटी की समानता का ढोल पीटा जाता है, विद्वान तर्क देते हैं, कवि कविताएँ लिखते हैं और सरकार योजनाएँ गिनाती है; वहीं दूसरी ओर, मानसिक हिंसा से जूझती स्त्रियाँ समाज की इन कुरीतियों से लड़ रही हैं या इसे ही अपनी नियति मानकर जी रही हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे 'सीखी हुई बेबसी' (Learned Helplessness) कहते हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति कई बार दोयम दर्जे से भी नीचे प्रतीत होती है। इन निमंत्रण पत्रों को देखकर यह एहसास होता है कि कई घरों में महिलाओं का स्थान पालतू जानवरों से भी नीचे है, जबकि वे हर उत्सव में बराबर की जिम्मेदारी निभाती हैं।

स्त्रियों के अस्तित्व का दूसरा बड़ा संघर्ष पैतृक संपत्ति के अधिकार को लेकर है। कानून बने लगभग 21 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार के पास महिलाओं को मिले संपत्ति अधिकार का सटीक आँकड़ा उपलब्ध नहीं है। शायद पुरुष-प्रधान सत्ता में बैठे लोगों को अपनी बहन-बेटियों को अधिकार देने की कोई जल्दी भी नहीं है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि बेटियों को 'दहेज' दे दिया गया, इसलिए संपत्ति पर उनका अधिकार नहीं बनता। यहाँ प्रश्न यह है कि क्या वह दहेज वास्तव में बेटी को मिलता है? क्या परिवार अपने बेटों की शादियों पर खर्च नहीं करते? और उनका क्या, जिन्हें दहेज भी नहीं मिला?

कहा जाता है कि बेटियों को मायके में सम्मान तभी मिलता है, जब वे संपत्ति में हिस्सा नहीं माँगतीं। क्या वास्तव में खाली हाथ मायके जाने वाली बेटियों को मान मिलता है? वास्तविकता तो यह है कि जो बेटी जितने मान-सम्मान के उपहार साथ लेकर आती है, उसे वैसा ही सत्कार मिलता है। यह व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है जैसा भाई-भाई या अन्य रिश्तेदारों के बीच होता है। इसका अर्थ है कि मायके में छोड़ी गई संपत्ति का स्त्रियों के पक्ष में कोई भावनात्मक महत्व नहीं रह जाता। जिस घर को वह अपना मानती थी और जिसे शादी के बाद अपना समझ रही थी, वे दोनों ही उसके नहीं होते। इस आघात को 'ट्रॉमेटिक रियलिटी शॉक' (Traumatic Reality Shock) कहते हैं, जिससे कई मानसिक और भावनात्मक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

अक्सर तर्क दिया जाता है कि संपन्न घर में ब्याही बेटी को भाई से हिस्सा क्यों लेना चाहिए? यहाँ दो बातें गौर करने वाली हैं। पहली–यह हिस्सेदारी भाई की संपत्ति में नहीं, बल्कि पिता की संपत्ति में होती है। पितृसत्तात्मक परवरिश में लड़कियों को 'पराया धन' और लड़कों को 'उत्तराधिकारी' माना जाता है, जिससे इस आर्थिक प्रताड़ना का सामान्यीकरण (Generalization) कर दिया जाता है। दूसरी बात–कितने संपन्न भाइयों ने अपनी बहन के लिए अपना हिस्सा छोड़ा है? एक संपन्न भाई अपने कमजोर भाई के लिए एक इंच जमीन नहीं छोड़ता और उसके लिए कोर्ट-कचहरी तक कर लेता है, जिसे समाज 'हक की लड़ाई' कहता है। किंतु यदि बहन अपने हिस्से की बात करे, तो उसे न जाने कितने अपमानजनक शब्दों से नवाज़ा जाता है।

यदि समाज में स्त्रियों को पूर्ण रूप से पैतृक संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो, तो उनके साथ होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा में भारी कमी आएगी। एक केस में एक महिला ससुराल में हिंसा इसलिए सह रही है क्योंकि उसका पूरा दिन दिव्यांग बच्चे की देखभाल में निकल जाता है। वह नौकरी नहीं कर सकती और उसके पास रहने के लिए मायके का सहारा भी नहीं है। भाई-बहन का भाई के लिए या बहन के लिए पैतृक संपत्ति का अधिकार छोड़ना किसी की अपनी इच्छा होनी चाहिए, मजबूरी नहीं।

तीसरा संघर्ष गृहणियों का है। बिना छुट्टी के काम करने वाली इन महिलाओं को पति के घर में भोजन और छत तो मिल जाती है, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिलता। यदि उन्हें उनके श्रम का पारिश्रमिक मिले, तो वे भी अपनी निर्णय क्षमता सिद्ध कर सकती हैं। जो स्त्रियाँ विमान उड़ा सकती हैं, उनमें उसे खरीदने की परख भी होगी। आज भी बड़े बजट की खरीदारी में महिलाओं की राय लेना पितृसत्तात्मक सोच को खटकता है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा, विवाह की आयु, संतान की संख्या, नौकरी का स्वरूप, पहनावा, मित्रता और यहाँ तक कि हँसने की मर्यादा भी अक्सर पिता, भाई, पति या पुत्र ही निर्धारित करते हैं। सबसे अधिक हिंसा उन्हीं महिलाओं के साथ होती है, जिनके मायके वालों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है। जिस घर में स्त्री ने जन्म लिया, जिसे अपना समझकर सहेजा, जब वहीं से उसे मानसिक रूप से तोड़ा जाता है, तो किसी अनजान घर में उसकी मजबूती की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आज अनगिनत महिलाएँ अपने अस्तित्व और नाम के लिए गुमनाम संघर्ष कर रही हैं। उनकी खामोशी भी एक संघर्ष है–अपने ही घर से अपना नाम मिटाए जाने के विरुद्ध एक मूक विद्रोह।

महिला दिवस विशेष

उनकी भूमिका

मोहन वर्मा

अपने जन्म से लेकर अन्तिम साँस तक
वे निभाती रहती हैं जीवन के रंगमंच पर
तरह-तरह की भूमिकाएं ।
हमारे चेहरे पर पल पल आने वाले, रंगों की तरह ही
बदलता रहता है
उनके जीवन का रंगबिरंगा या बदरंगा कैनवास ।

कहीं जनम पर अनचाही-करमजली कहकर
पल पल लड़की होने का एहसास दिलाया जाता रहा उन्हें
तो कहीं लक्ष्मी मानकर दुलार की बरसात भी की गई

होश संभालते और समझ आते आते
वे कब सीख गई भेड़ और भेड़ियों मे फर्क़
वे खुद नहीं जानती
लड़की होने की अपनी नियति से अभिशप्त
गर्दन झुकाये चली जाती हैं वे
अपनों के बीच से परायों के बीच

और भला बुरा सब कुछ स्वीकार लेती हैं
भाग्य का लिखा मानकर
खपा देती हैं अपनी सारी उम्र- एक नये संसार में ।

बचपन में कई बार माँ-पिता के अबोले में
अपनी मासूमियत और उम्र से ज्यादा समझदारी से
सुलह कराती या फिर भाई का बचाव करती वे
अपनी उसी समझदारी से करते रहती मध्यस्थता
पिता और पुत्र के बीच भी-उनकी अनबन में
बनकर उनका निवाला-जब वे कहते ÷भूख नहीं है÷।

घर के रिश्तों और भावनाओं को
एक मजबूत डोर से बाँधकर रखती हैं वे
बहू से सास बन जाने के बाद भी /बरसों बरस घर
उनके मजबूत कंधों के भरोसे निश्चिंत रहता है
और निश्चिंत रहते है वे सब भी-
जिनके भरोसे घर - घर माना जाता है ।

और एक दिन यकायक
नाटक के निर्देशक के इशारों पर
जीवन के रंगमंच पर खत्म हो जाती है उनकी भूमिका
कि अचानक एहसास होता है उनके न होने का
एक अंतहीन उदासी पसर जाती है
जब बोलती दीवारें बोलना बन्द कर देती है
खिले फूल दिखाई देने लगते हैं बेज़ान से
रंग हो जाते हैं बेरंग
क्योंकि लौट जाती हैं वे अपने सारे रंग समेटकर
जीवन के रंगमंच पर ख़त्म हो जाती है उनकी भूमिका ।।

औरतें, घर से बाहर

रामेश्वरम तिवारी

औरतें पढ़-लिखकर
अवनि को नापने लगी हैं
अंबुधि को मथने लगी हैं
परिंदों-सी अपने पर फैलाकर
सरहदों को लाँघकर
अंबर में उड़ान भरने लगी हैं।

जो मृगी कल तक
भयाक्रांत थी आखेटकों से
आज खुद आखेटकों का
आखेट करने में लगी हुई हैं।

गर्व से सिर ऊँचाकर
घूँघट के पट खोलकर
सबको दिखा देना चाहती है
वह किसी भी नज़रिए से
आदमी के पीछे नहीं
वरन् कँधा मिलाकर खड़ी हैं।

उसने आज़ादी का
अमृत आस्वादन कर लिया है
सालों-सदियों की
दासता की ज़ंजीरें तोड़कर
घर से बाहर निकल आयी हैं।

महिला दिवस

महिलाओं की सुरक्षित सहभागिता का समय

संध्या अग्रवाल
लेखक साहित्यकार हैं।

हर वर्ष महिला दिवस पर सम्मान और सशक्तिकरण की बातें ज़ोर-शोर से होती हैं। पर क्या सचमुच महिलाओं का दैनिक जीवन उतना ही सुरक्षित और सम्मानजनक है, जितना मंचों से बताया जाता है? यही वह प्रश्न है, जो उत्सव के बीच भी हमें ठहरकर सोचने को मजबूर करता है।

हर वर्ष महिला दिवस आते ही सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण की चर्चाएँ तेज़ हो जाती हैं। मंच सजते हैं, भाषण होते हैं और उपलब्धियों के उदाहरण गिनाए जाते हैं। लेकिन असली प्रश्न आज भी वही है – क्या महिलाओं का रोज़मर्रा का जीवन उतना ही सुरक्षित, सम्मानपूर्ण और अवसरपूर्ण बन पाया है, जितना इन मंचों पर दिखाई देता है? आधी आबादी की वास्तविक और सुरक्षित सहभागिता के बिना किसी भी समाज का संतुलित विकास संभव नहीं।

निस्संदेह पिछले वर्षों में शिक्षा, रोजगार, प्रशासन और उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। छोटे शहरों और कस्बों की बेटियाँ अब सीमाएँ तोड़कर अपनी पहचान बना रही हैं। स्वयं सहायता समूहों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरकारी योजनाओं ने आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में नए रास्ते खोले हैं। यह परिवर्तन समाज में सकारात्मक चेतना का संकेत है।

फिर भी चुनौती केवल अवसर उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि सामाजिक सोच बदलने की है। आज भी अनेक परिवारों में लड़की की शिक्षा को निवेश नहीं बल्कि खर्च माना जाता है। कार्यस्थलों पर सुरक्षा, समान अवसर और निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी जैसे प्रश्न पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में तो कई प्रतिभाएँ सामाजिक दबाव और असुरक्षा की भावना के कारण आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाती हैं।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल नौकरी या आय नहीं, बल्कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण वातावरण है। जब घर में बेटी की राय सुनी जाएगी, स्कूल में उसे बराबरी का मंच मिलेगा और समाज उसकी उपलब्धियों को सहज रूप से स्वीकार करेगा, तभी वास्तविक परिवर्तन दिखाई देगा।

इस दिशा में शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है। केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि जीवन कौशल, डिजिटल साक्षरता और आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी उतने ही आवश्यक हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि रहे, और उसी के साथ उन्हें अवसर तथा विश्वास भी मिले। सुरक्षित वातावरण ही उन्हें आगे बढ़ने का वास्तविक आत्मबल देता है।

महिला दिवस को केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित रखने के बजाय इसे सामाजिक आत्ममंथन का अवसर बनाया जाना चाहिए। यदि परिवार, संस्थाएँ और समाज मिलकर सुरक्षा, समान अवसर और सम्मान की संस्कृति विकसित करें, तो सशक्तिकरण किसी विशेष दिन का विषय नहीं रहेगा, बल्कि सामान्य जीवन व्यवहार बन जाएगा। महिलाओं की प्रगति केवल उनका अधिकार नहीं, समाज की आवश्यकता है। जब सुरक्षा, अवसर और विश्वास साथ चलेंगे, तभी सशक्तिकरण सचमुच जीवन में उतरेगा।

व्यंग्य

भाषा की मर्दानगी और महिला सशक्तिकरण का व्याकरण

सुदर्शन कुमार सोनी
लेखक व्यंग्यकार हैं।

संसद तक शब्दों की गद्दी पर पुरुष बैठे रहेंगे, बराबरी की कुर्सी हमेशा फोल्डिंग ही रहेगी। हर साल अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश में महिला सशक्तिकरण की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। मंच सजते हैं, भाषण होते हैं, और समाज गर्व से घोषणा करता है कि अब महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इस पूरे उत्सव के बीच एक छोटी-सी समस्या चुपचाप मुस्कुरा रही होती है–हमारी भाषा। क्योंकि भाषा का लोकतंत्र भी अजीब है–वोट सबके बराबर हैं, लेकिन शब्दों की कुर्सी पुरुषों के लिए आरक्षित है।

दरअसल असली खेल संसद विधानसभाओं या समाज में नहीं, शब्दकोष में खेला गया है। शब्द इतने चतुराई से बनाए गए हैं कि पुरूषोचित चौधराहट ही हमेशा छायी रहे । उदाहरण के लिए 'पुरुषार्थ' शब्द को ही देख लीजिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष–ये जीवन के चार लक्ष्य बताए गए। लेकिन इनका नाम पड़ा पुरुषार्थ। अब अगर कोई स्त्री वही सब हासिल कर ले तो क्या कहेंगे? 'स्त्रीयार्थ'? यह शब्द तो किसी को याद नहीं आता। पुरुषार्थ का मतलब ही बता देता है कि सफलता का पेटेंट किसके नाम लिखा गया है।स्त्री अपने दम पर आईएएस भी बन जाए तो कहेंगे कि उसने पुरूषार्थ का परिचय दिया। रामचरितमानस को सीताचरितमानस क्यों नही कहा गया।करवा चौथ का विधान कर पतिव्रता शब्द गढ़ दिया , पत्नीव्रती क्यों भेजे मे नही आया।भाषा का संविधान भी बड़ा दिलचस्प है। ऊपर से बराबरी लिखी है, लेकिन नीचे फुटनोट में लिखा रहता है–'शर्तें लागू'। यानि पुरुषों का वीटो लगा हुआ है।

अब 'मसीहा' शब्द को ही देख लीजिए। संकट आए तो लोग कहते हैं–कोई मसीहा आएगा और सब ठीक कर देगा। लेकिन यह मसीहा अपने आप पुरुष ही क्यों होता है? ÷मसीही÷ शब्द किसी को याद नहीं आता। लगता है जैसे भाषा ने तय कर लिया हो कि उद्धार का ठेका पुरुषों के पास ही रहेगा। भाषा की यह चालाकी ताकत के शब्दों में और साफ दिखती है। 'पहलवान' शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में मूंछों वाला एक भारी-भरकम आदमी उभर आता है। लेकिन अगर वही ताकत किसी महिला में दिख जाए तो तुरंत उसके आगे 'महिला' जोड़ना पड़ता है–पहलवान अगर पुरुष है तो बस पहलवान, और अगर स्त्री है तो पहले 'महिला' जोड़कर अनुमति लेनी पड़ेगी।

पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है कन्या रत्न की कभी नही। पुत्री अच्छा कार्य करे तो मेरा बेटा हो जाती है पुत्र अच्छा कार्य करे तो मेरी बेटी कंहा गयी। और सबसे दिलचस्प मामला है 'वेश्या' शब्द का। अगर वही काम पुरुष करे तो भाषा अचानक शर्मीली हो जाती है। उसके लिए कोई लोकप्रिय शब्द नहीं मिलता।

असल में भाषा सीधे-सीधे भेदभाव नहीं करती, बस धीरे-धीरे समझा देती है कि किसकी गलती गलती नहीं है और किसकी मजबूरी भी अपराध है। इसलिए भाषा इतनी समझदार है कि पुरुष की गलती भी 'शरारत' बन जाती है और स्त्री की मजबूरी 'चरित्र' बन जाती है।

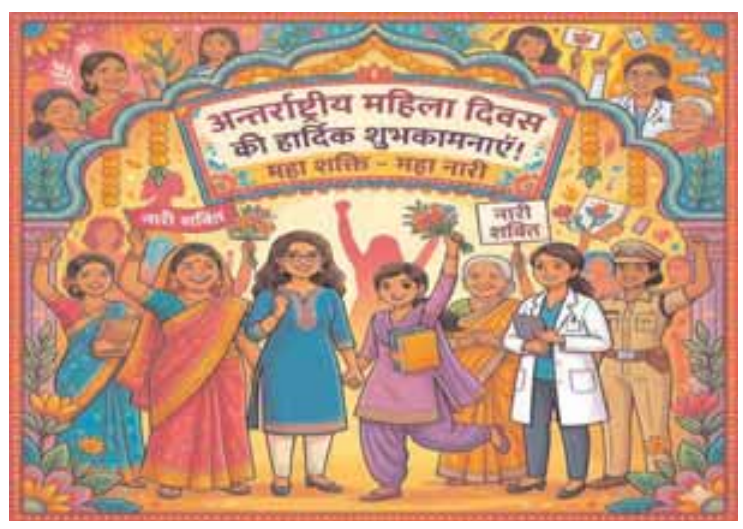

सत्तासुंदरी के शब्दों में भी यही कहानी दिखाई देती है। किसी महिला को देश का सर्वोच्च पद मिल जाए तो वह राष्ट्रपति ही कहलाती है। लेकिन जैसे ही नीचे की कुर्सियों की बात आती है, लोग ÷मंत्राणी÷, 'नेत्री', 'अध्यक्षा' जैसे प्रयोग करने लगते हैं। मानो भाषा कह रही हो–ऊपर तक तो ठीक है, लेकिन नीचे आते-आते पहचान अलग करनी पड़ेगी।

इसी तरह 'अधिकारी' शब्द है। महिला भी अधिकारी ही कहलाती है, लेकिन 'अधिकारिणी' शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी संस्कृत नाटक की पंक्ति सुन ली हो। भाषा का यह खेल इतना महीन है कि हमें पता भी नहीं चलता और बराबरी धीरे-धीरे फाइलों में अटक जाती है। शब्दकोष में बराबरी ढूँढना वैसा ही है जैसे त्वरित न्याय। है।गंगाधर को एक और पीड़ा है कि स्त्री इसके लिए बिल्कुल भी सजग नही है। वह तो महिला दिवस के आयोजन से ही अभिभूत है। सुंदरकांड का आयोजन कर पुरूषों के साथ उत्साह पूर्वक ढोर गंवार शूद्र व नारी ये सभी ताड़न के अधिकारी पंक्ति भी गाती है ।

इस पूरे मामले की असली विडंबना यह है कि समाज ने महिलाओं को मंच तो दे दिया, माइक्रोफोन भी थमा दिया, लेकिन शब्दों की चाबी अब भी पुरुषों के पास है। समाज ने महिलाओं को पंख तो दिए, लेकिन उड़ान का शब्दकोष अब भी पुरुषों के पास है।

यही वजह है कि महिला सशक्तिकरण की असली लड़ाई संसद, अदालत या सड़क पर नहीं, बल्कि भाषा के अंदर चलनी चाहिए। भाषा के अनेक शब्द तो स्त्री को कदम-कदम पर छलनी करते हैं। क्योंकि महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी बाधा पुरुष नहीं, बल्कि पुरुषों द्वारा बनाया गया शब्दकोष है।

और जब तक शब्दों की गद्दी पर वही पुराने मालिक बैठे रहेंगे, तब तक बराबरी की कुर्सी स्थायी नहीं होगी। हमेशा फोल्डिंग ही रहेगी। स्त्रियों हर जगह आप शब्दों की बेड़ियों में हो आपको कुछ और नही केवल इसे तोड़ना है बाकी कार्य अपने आप हो जाएगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।
प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

डिजिटल दुनिया

ममता कुशवाहा

लेखक शिक्षक हैं।

महिलाओं की बढ़ती उड़ान और सामने खड़ी चुनौतियाँ

डिजिटल युग ने मानव जीवन के लगभग हर क्षेत्र को गहराई से प्रभावित किया है। संचार, शिक्षा, व्यापार, शासन और सामाजिक संबंधों के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आया है। इंटरनेट के तीव्र प्रसार, नई तकनीकों के विकासऔर डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विस्तार ने दुनिया भर के लोगों के लिएअभूतपूर्व अवसर पैदा किए हैं। इस बदलते दौर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि महिलाओं की डिजिटल क्षेत्र में भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आज महिलाएँ केवल तकनीक का उपयोग करने वाली उपभोक्ता भर नहीं रह गई हैं,बल्कि वे नवाचार करने वाली, उद्यमी, शिक्षिका और नेतृत्वकारी भूमिकानिभाने वाली सक्रिय शक्ति बनती जा रही हैं। वे डिजिटल दुनिया के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। फिर भी इन सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद महिलाओं को कई सामाजिक, संरचनात्मक और तकनीकीचुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो डिजिटल क्षेत्र में उनकी पूर्णभागीदारी को सीमित करती हैं।

डिजिटल युग में महिलाओं की भागीदारी का सबसे स्पष्ट रूप शिक्षा और जानकारी तक उनकी बढ़ती पहुँच में दिखाई देता है। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म, डिजिटल पुस्तकालय, वेबिनार और वर्चुअल कक्षाएँ महिलाओं और लड़कियों के लिए ज्ञान प्राप्त करने के नए द्वार खोल रही हैं। पहले अनेक महिलाएँ पारिवारिक जिम्मेदारियों, सामाजिक प्रतिबंधों या आर्थिक सीमाओंके कारण विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक नहीं पहुँच पाती थीं। लेकिन आज इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के माध्यम से वे घर बैठे ही नई-नई जानकारियाँप्राप्त कर सकती हैं और अपने कौशल का विकास कर सकती हैं। इससे न केवलउनके ज्ञान का विस्तार हुआ है बल्कि उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरताभी बढ़ी है। डिजिटल शिक्षा ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एकमहत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था ने भी महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों के नए रास्तेखोले हैं। ई- कॉमर्स वेबसाइटें, ऑनलाइन बाजार और डिजिटल भुगतानप्रणालियाँ महिलाओं को कम निवेश में अपना व्यवसाय शुरू करने की सुविधा प्रदान कर रही हैं। आज अनेक महिलाएँ घर से ही अपने बनाए हुए उत्पाद, जैसेहस्तशिल्प, कपड़े, घरेलू वस्तुएँ या अन्य सेवाएँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेच रही हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के साधनों की सहायता से वे अपने ग्राहकों तक दूर-दूर तक पहुँच बना पा रही हैं। इससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर मिल रहा है और वे परिवार की आय में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस प्रकार डिजिटल माध्यमों के कारणमहिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ रही है और धीरे-धीरे समाज में पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं में भी बदलाव दिखाई देने लगा है।

तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी महिलाओं की उपस्थिति धीरे-धीरे मजबूतहोती जा रही है। आज महिलाएँ सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा विश्लेषक, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, डिजिटल मार्केटर और तकनीकी शोधकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। कई महिलाएँ बड़ी तकनीकी कंपनियों, स्टार्टअप्स और डिजिटलपरियोजनाओं का नेतृत्व भी कर रही हैं। उनके विचार और दृष्टिकोण तकनीकी विकास को अधिक विविध और रचनात्मक बना रहे हैं। विश्व भर की सरकारें औरअंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ भी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्नयोजनाएँ और कार्यक्रम चला रही हैं, ताकि तकनीकी क्षेत्रों में मौजूदलैंगिक असमानता को कम किया जा सके।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी महिलाओं को अपनी बात रखने और समाज सेजुड़ने का एक सशक्त माध्यम प्रदान किया है। आज महिलाएँ डिजिटल मंचों केमाध्यम से सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाती हैं, अपने अनुभव साझा करतीहैं, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी देती हैं और लैंगिक समानता की वकालत करती हैं। महिलाओं के अधिकार, कार्यस्थल पर समान अवसर और सामाजिक न्याय से जुड़े कई आंदोलन डिजिटल माध्यमों के कारण वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बने हैं। सोशल मीडिया ने महिलाओं को अपनी आवाज़ को व्यापक समाज तक पहुँचाने का अवसर दिया है, जिससे सार्वजनिक विमर्श परउनका प्रभाव बढ़ा है।

हालाँकि इन सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद डिजिटल युग में महिलाओं कीभागीदारी अभी भी समान और संतुलित नहीं है। इसके सामने कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। सबसे बड़ी समस्या डिजिटल लैंगिक अंतर (डिजिटल जेंडर डिवाइड) की है। दुनिया के कई हिस्सों, विशेषकर विकासशील देशों में, महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाएँ कमउपलब्ध हैं। आर्थिक असमानता, सामाजिक मान्यताएँ और पारिवारिक प्रतिबंध कईबार महिलाओं को डिजिटल तकनीक के उपयोग से दूर रखते हैं। कुछ रूढ़िवादी समाजों में परिवार महिलाओं के इंटरनेट उपयोग को लेकर संदेह या डर कीभावना रखते हैं, जिससे उनकी डिजिटल दुनिया तक पहुँच सीमित हो जाती है। इसप्रकार तकनीक तक समान पहुँच न होने के कारण महिलाएँ डिजिटल अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पातीं।

एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर उत्पीड़न की समस्या है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को अक्सर अपमानजनक टिप्पणियों, ट्रोलिंग, धमकियों और पीछा करने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से महिला पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी महिलाएँ कई बार संगठित ऑनलाइन हमलों का लक्ष्य बन जाती हैं। ऐसी परिस्थितियाँ कई महिलाओं को अपनी राय खुलकर व्यक्त करने से रोक देती हैं। लगातार होने वाला साइबर उत्पीड़न मानसिक तनाव, भय और असुरक्षा की भावना को जन्म देता है, जिससे कई महिलाएँ डिजिटल मंचों से दूरी बना लेती हैं।

तकनीकी नेतृत्व में महिलाओं की कम उपस्थिति भी एक गंभीर चिंता का विषय है। हालाँकि तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, फिर भी उच्च नेतृत्व पदों पर उनकी भागीदारी अभी भी सीमित है। कई बार लैंगिकभेदभाव, असमान अवसर और कार्यस्थल पर पक्षपात जैसी स्थितियाँ महिलाओं के करियर विकास में बाधा बनती हैं। वेतन असमानता, मार्गदर्शन की कमी और सहयोगी कार्य वातावरण का अभाव भी महिलाओं के सामने चुनौतियाँ खड़ी करता है। इन संरचनात्मक बाधाओं को दूर किए बिना तकनीकी क्षेत्र में वास्तविक लैंगिक समानता स्थापित करना कठिन है।

डिजिटल साक्षरता की कमी भी महिलाओं की प्रगति में एक महत्वपूर्ण बाधा है। तकनीक तक पहुँच होना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी है उसका सही और प्रभावी उपयोग करना आना। ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों की कई महिलाएँ डिजिटल उपकरणों, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने में प्रशिक्षित नहीं होतीं। इसके कारण वे डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ने और उससे लाभ प्राप्त करने के अवसरों से वंचित रह जाती हैं। इसलिए सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों को महिलाओं और लड़कियों के लिए विशेष डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है।

सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएँ भी कई बार महिलाओं की डिजिटल भागीदारी को प्रभावित करती हैं। अनेक समाजों में महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें और पेशेवर या तकनीकी क्षेत्रों में कम समय दें। ऐसी सामाजिक धारणाएँ महिलाओं को नए अवसरों की खोज से रोकती हैं। इसके अलावा यह रूढ़िवादी धारणा भी प्रचलित है कि तकनीक का क्षेत्र केवल पुरुषों के लिए उपयुक्त है। यह सोच कई लड़कियों को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने से हतोत्साहित करती है। इन रूढ़ियों को बदलने के लिए शिक्षा, जागरूकता और सकारात्मक सामाजिक वातावरण की आवश्यकता है।

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकारों, तकनीकी कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करने होंगे। सरकारों को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो सस्ती इंटरनेट सेवाएँ, मजबूत डिजिटल ढाँचा और लैंगिक समानता को बढ़ावा दें। तकनीकी कंपनियों को ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने चाहिए जो उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित हों और साइबरउत्पीड़न को रोकने के प्रभावी उपाय प्रदान करें। शैक्षणिक संस्थानों कोलड़कियों को विज्ञान और तकनीक के विषयों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उन्हें मार्गदर्शन तथा अवसर प्रदान करने चाहिए।

सामुदायिक स्तर पर चलाए जाने वाले कार्यक्रम भी महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डिजिटल कौशल, ऑनलाइन व्यवसाय और साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उन्हें नई संभावनाओं से जोड़ते हैं। जब महिलाएँ डिजिटल रूप से सशक्त होती हैं तो वे केवल अपने जीवन में ही परिवर्तन नहीं लातीं, बल्कि अपने परिवार और समुदाय के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अनेक अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के व्यापक विकास को गति देता है, जिससे बच्चों की शिक्षा बेहतर होती है, स्वास्थ्य सेवाएँ सुधरती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।

डिजिटल युग महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, नवाचार और नेतृत्व के अनेक अवसर लेकर आया है। शिक्षा, उद्यमिता, तकनीक और सामाजिक जागरूकता जैसे क्षेत्रों में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। फिर भी डिजिटल समानता की दिशा में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। डिजिटल अंतर, साइबर उत्पीड़न, नेतृत्व में कम प्रतिनिधित्व और डिजिटल साक्षरता की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। इन समस्याओं का समाधान सामूहिक प्रयासों और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता से ही संभव है। यदि महिलाओं को डिजिटल दुनिया में समान अवसर, संसाधन और सुरक्षा प्रदान की जाए, तो वे एक अधिक समावेशी, रचनात्मक और न्यायपूर्ण भविष्य के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

महिला दिवस पर विशेष

चित्रा माली

सहायक प्रोफेसर गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि केंद्र, कोलकाता।

'गिव टू गेन' की थीम और महिला दिवस के मायने

भारत में नारीवादी संगठनों के द्वारा 8 मार्च 1980 को महिलाओं के साथ होने वाले सबसे घृणित अपराध/हिंसा बलात्कार के विरुद्ध मार्च निकाला गया था। जिसमें नारीवादी संगठनों के सदस्यों के साथ यूनिवर्सिटी,कॉलेज के छात्र और छात्राएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इसके पूर्व 1978 में हैदराबाद में 'रमिज़ा बी' के साथ हुए बलात्कार और उसके पति की निर्मम हत्या की जांच के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था। जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया था लेकिन सत्र न्यायालय ने उन्हें छोड़ दिया था। सत्र न्यायालय के इस निर्णय का विरोध महिला संगठनों के द्वारा किया गया था। 1979 में महिला संगठनों ने बलात्कार के विरोध में गुवाहाटी में रैलियां आयोजित की थीं। सामूहिक बलात्कार के विरोध में संथाल परगना (झारखंड) में भी अभियान चलाया गया था। भारत में बलात्कार के मुद्दे को 70 के दशक के अंत में सार्वजनिक एजेंडे में तब रखा गया था जब महिला समूहों और संगठनों ने महाराष्ट्र में एक आदिवासी लड़की मथुरा के पुलिस बलात्कारियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आवाज उठाई थी। जिसे हम 'मथुरा कांड' या 'मथुरा बलात्कार कांड' के नाम से जानते हैं। न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ चार वरिष्ठ वकीलों ने एक खुला पत्र लिखा था जिससे प्रेरित होकर बंबई के नारीवादी संगठन फोरम अगेंस्ट रेप (जो अब खुद को फोरम अगेंस्ट आप्रेसन ऑफ वीमेन कहता है) मंच ने इस मामले को दुबारा खुलवाने का निर्णय लेते हुए देश के समस्त महिला संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पत्र लिखा। पत्र पर अमल करते हुए देशभर के नारीवादी संगठन पहली बार किसी राष्ट्रव्यापी अभियान में एक साथ शामिल हुए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महिला हिंसा और बलात्कार का विरोध 70 के दशक से ही शुरू हुआ। वैश्विक स्तर पर पहला 'रिक्लेम द नाइट आंदोलन' 12 नवंबर 1977 को लीड्स में हुआ था जिसके अंतर्गत विरोध प्रदर्शन मार्च का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन लीड्स क्रांतिकारी नारीवादी समूह के द्वारा किया गया था। जिसकी प्रेरणा जर्मनी में 30 अप्रैल 1977 को बलात्कार और महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के विरोध में कई शहरों में निकाले गए मार्च से ली गई थी। इसके पूर्व 70 के दशक में ही अमेरिका के फिलाडेल्फिया में 1975 में जब सुसान 'सू' अलेक्जेंडर स्पीथ की हत्या काम से घर लौटते समय कर दी गई थी तब इस घटना के विरोध में नारीवादी समूह 'वीमेन अगेंस्ट वायलेंस एंड पोर्नोग्राफी इन मीडिया' ने भी एक सम्मेलन का आयोजन किया था और बाद में विरोध मार्च निकाला था। 'रिक्लेम द नाइट आंदोलन' 'यॉर्कशायर रिपर' हत्याकांड और पुलिस द्वारा महिलाओं को दिए गए निर्देश के खिलाफ था जिसमें महिलाओं को रात के बाद सार्वजनिक स्थानों से दूर रहने के लिए की नसीहत दी गई थी। लीड्स में मार्च दो स्थानों से शुरू हुआ पहला चैपलटाउन से जिसमें 30 महिलाओं ने हिस्सा लिया और दूसरा वुडहाउस से जिसमें 85 महिलाओं ने सहभागिता की थी। इसके अतिरिक्त लीड्स क्रांतिकारी समूह की महिलाओं के प्रयासों से इसी रात इन शहरों में यॉर्क, ब्रिस्टल, ब्राइटन, न्यूकैसल, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, लैंकेस्टर और लंदन में भी विरोध मार्च हुए थे। इसी प्रकार की नसीहतें भारत में भी महिलाओं को दी जातीं रही हैं और साथ ही कपड़ों से लेकर रहन सहन के तरीकों पर भी विशेष ज्ञान दिया जाता रहा है लेकिन हमारे यहां इन नसीहतों के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन या मार्च का आयोजन नहीं किया जाता है क्योंकि इन सब तरह की नसीहतों को सोशल कंडीशनिंग के चलते हम सुरक्षा और संरक्षण के लिहाज से स्वीकार करते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा में कोई कमी नहीं आयी है। सोहो में 1978 में हुए एक मार्च के दौरान महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी जिसमें कई महिलाएं घायल हुई और पुलिस ने 13 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद सोहो में ही एक वर्ष बाद आयोजित मार्च में 2,000 महिलाओं ने भाग लिया था। इसमें महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा,बलात्कार और सार्वजनिक स्थानों पर निर्बाध रूप से आवागमन के लिए, महिलाओं के एक साथ आने के महत्व पर जोर दिया गया था।

1987 बेलफ़ास्ट में 'रिक्लेम द नाइट' मार्च विरोध प्रदर्शन हुआ था। यह मार्च सिटी हॉल तक किया गया था और इसमें बेलफ़ास्ट रेप सेंटर व स्ट्रैनमिलिस कॉलेज सहित विभिन्न संगठनों की महिलाएं शामिल थीं। 1990 के दशक में 'रिक्लेम द नाइट' आंदोलन के अंतर्गत होने वाले विरोध प्रदर्शन बंद हो गए थे। वर्ष 2004 में नारीवादी संगठनों ने 'रिक्लेम द नाइट आंदोलन' और प्रदर्शन को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। इस वर्ष,लंदन में आयोजित प्रदर्शन में केवल 30 महिलाएं ही शामिल हुईं, लेकिन अगले वर्ष 2005 में लगभग 1,000 महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। 2006 में पांच यौनकर्मियों की हत्याओं के जवाब में इप्सविच में 'रिक्लेम द नाइट' विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। जिसमें 200 से 300 लोग शामिल हुए थे। बर्मिंघम में पहला 'रिक्लेम द नाइट' मार्च अक्टूबर 2009 में हुआ था। वर्ष 2010 लंदन में 2500 महिलाओं ने शहर में मार्च किया था और लीड्स में 200 से अधिक महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन मार्च किया था। वर्ष 2013 में नॉर्थम्पटन में पहला 'रिक्लेम द नाइट' मार्च हुआ था, जिसमें पुरुषों को भी भाग लेने की अनुमति दी गई थी। मार्च का उद्देश्य नॉर्थम्पटनशायर रेप एंड इनसेस सेंटर (एनआरआईसीसी) के लिए जागरूकता को बढ़ाना भी था। वर्ष 2017 में #MeToo आंदोलन से प्रेरित सैकड़ों महिलाओं ने लंदन,ब्रिस्टल,न्यूकैसल और यूनाइटेड किंगडम में मार्च किए थे। वर्ष 2021 में सारा एवरार्ड की मृत्यु के विरोध में लीड्स में एक कैंडल मार्च आयोजित करने की कोशिश की गई थी,लेकिन इसे पुलिस द्वारा रोक दिया गया था। जिससे विरोध प्रदर्शन आभासी माध्यम से (ऑनलाइन) हुआ और इसमें 28,000 से अधिक लोगों ने शिरकत की,जिसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर स्ट्रीम किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार 'रिक्लेम द नाइट' मार्च 1978 में आयोजित किए गए,जो पहले पर्थ और सिडनी में हुए थे और फिर 1979 में मेलबर्न में हुए थे। वर्ष 2017 लजुब्लजियाना में 'रिक्लेम द नाइट' विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। वर्ष 1978 में, अमेरिका में पहली बार 'रिक्लेम द नाइट' मार्च का आयोजन किया गया था। जिसमें 50 राज्यों की 5,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। भारत में वर्ष 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद 'रिक्लेम द नाइट' रात को पुनः प्राप्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन मार्च हुए थे। विरोध प्रदर्शन के लिए नव-वर्ष की पूर्व संध्या को चुना गया था। इस दिन 20 अलग-अलग शहरों में सैकड़ों महिलाओं ने सामूहिक बलात्कार के विरोध में मार्च प्रदर्शन और कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसके बाद भारत में ही वर्ष 2024 में पश्चिम बंगाल, कोलकाता में हुए बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में हजारों महिलाओं और पुरुषों ने 'रिक्लेम द नाइट' मार्च 'मेयरा रात डोखोल कोरो' (रिक्लेम द नाइट का बांग्ला अनुवाद) रात को पुनः प्राप्त करने के लिए मार्च और कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जिस प्रकार से निर्भया कांड के लिए विरोध प्रदर्शन के लिए नव-वर्ष की पूर्व संध्या को चुना गया था उसी प्रकार से आर.जी.कर कोलकाता की घटना के विरोध प्रदर्शन के लिए स्वतंत्रता दिवस की पूर्व रात्रि यानी 14 अगस्त 2024 को 11.55 पर मार्च का समय निर्धारित किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन मार्च के लिए भी सोशल मीडिया पर अपील जारी की गई थी और बहुत ही कम समय में अलग-अलग स्थानों पर एकत्रित होकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन मार्च निकाले थे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला हिंसा और बलात्कार के विरोध प्रदर्शन और प्रतिरोध के संघर्ष को शामिल करने का उद्देश्य महज इतना है कि महिला हिंसा और बलात्कार के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों, अधिनियमों को बनवाने के लिए और रात को पुनः प्राप्त करने के लिए (रिक्लेम द नाईट) नारीवादी संगठनों ने और महिलाओं ने लंबा संघर्ष किया है और कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन समाज व्यवस्था में दिखाई नहीं देता है। आज भी पीड़िता के लिए न्याय की प्रक्रिया बहुत जटिल है और दुरूह है तथा न्याय प्राप्ति में भी लंबा समय लगता है इसलिए बहुत कम महिलाएं ही अपने साथ होने वाले अपराध की प्राथमिकी दर्ज करती हैं और न्याय के लिए संघर्ष करती हैं। कमाल की बात तो यह भी है कि हमारे देश में न्याय मिलने के बाद भी पीड़िता को न्याय को बरकरार रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर बिलकिस बानो और उन्नाव रेप केस की पीड़िता को लिया जा सकता है जिन्होंने न्याय को बरकरार रखने के लिए दुबारा संघर्ष किया है। निर्भया कांड पर दिल्ली क्राइम वेब सीरीज सीजन एक,उन्नाव रेप केस पर सिया और ऐसी कई फिल्में और वेब सीरीज महिला हिंसा और बलात्कार पर बनाई गई है। 20 फरवरी को फिल्म 'अस्सी' रिलीज हुई है जो इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध करती दिखाई देती है। इस साल के प्रारंभ में ही मणिपुर में सामूहिक दुष्कर्म (वर्ष 2023 मई) की शिकार हुई एक 20 वर्षीय युवती ने दम तोड़ दिया था। पीड़िता की बहन ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कहा था कि 'कोई उसे न्याय नहीं दिला सका'। यह वाक्य पूरी न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिंह लगाता है और साथ ही यह सोचने पर विवश भी करता है कि क्या भारत में पीड़िता को समय पर न्याय मिलता है?

इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रात को पुनः प्राप्त करने के अधिकार के लिए संघर्ष किया जाए जो आजादी के इतने वर्षों बाद भी आधी आबादी को नसीब नहीं हो पाई है आज भी वे अपने समानता और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम 'गिव टू गेन' है जिसका मतलब जब हम देते हैं, तो हमें मिलता है। आधी आबादी ने पुरुषों को बिना किसी संघर्ष के सभी अधिकार प्रदान किए हैं, तो अब पुरुषों से भी यह उम्मीद की जानी चाहिए कि वे भी आधी आबादी को अपने अधिकारों का उपभोग करने देंगे। यह एक वर्ष भर चलने वाला अभियान है जो लैंगिक समानता को हासिल करने में बढ़ावा देने की मानसिकता को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

महिला दिवस विशेष

डॉ. मनीष जैसल

लेखक मीडिया शिक्षक हैं।

महिलाओं ने खुद बदली है अपनी दुनिया

भारतीय समाज की संरचना लंबे समय तक ऐसी रही जिसमें महिलाओं की भूमिका को मुख्यतः घर और परिवार तक सीमित मान लिया गया था। सदियों तक सामाजिक मान्यताओं, रूढ़ियों और परंपराओं ने यह धारणा बनाए रखी कि सार्वजनिक जीवन, निर्णय-निर्माण और नेतृत्व के क्षेत्र पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। लेकिन इतिहास की गति स्थिर नहीं रहती। समय के साथ-साथ महिलाओं ने केवल इन सीमाओं को चुनौती ही नहीं दी, बल्कि उन्हें तोड़कर अपनी दुनिया को नए अर्थ दिए। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, यह शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक आंदोलनों और व्यक्तिगत साहस के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है। आज राजनीति, विज्ञान, खेल, कला, सिनेमा, संगीत और स्वास्थ्य जैसे लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी दिखाई देती है। यह केवल प्रतिनिधित्व का विस्तार नहीं, बल्कि यह उस सोच का परिवर्तन भी है जिसमें महिला को केवल सहायक भूमिका में देखा जाता था। आधुनिक भारत की अनेक महिलाएँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने काम और संघर्ष से यह साबित किया है कि प्रतिभा और नेतृत्व किसी एक लिंग की बपौती नहीं है।

अगर हम राजनीति की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। 1952 की पहली लोकसभा में कुल 489 सांसदों में केवल 22 महिलाएँ थीं, यानी लगभग 4.5 प्रतिशत। लंबे समय तक यह संख्या बहुत धीमी गति से बढ़ती रही। लेकिन हाल के वर्षों में स्थिति बदलती दिखाई देती है। 2019 की लोकसभा में 78 महिलाएँ चुनी गईं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है और कुल सदस्यों का लगभग 14 प्रतिशत है। इस बदलाव के पीछे अलग-अलग राज्यों की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। पश्चिम बंगाल इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जहाँ से संसद में लगातार बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधि पहुँचती रही हैं। बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी जैसी नेता ने न केवल एक सशक्त क्षेत्रीय नेतृत्व स्थापित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि जमीनी संघर्ष से राजनीति की दिशा बदली जा सकती है। संसद में भी पश्चिम बंगाल से महुआ मोइत्रा और नुसरत जहाँ जैसी महिला सांसदों ने अपने सक्रिय हस्तक्षेप से राष्ट्रीय बहसों को प्रभावित किया है। बिहार से मीसा भारती और ओडिशा से अपराजिता सारंगी जैसी सांसदों ने भी अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों के साथ संसद में योगदान दिया है। भारतीय राजनीति के इतिहास में इंदिरा गांधी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में लंबे समय तक देश का नेतृत्व किया और उस दौर में महिलाओं की राजनीतिक क्षमता को लेकर बने कई पूर्वाग्रहों को तोड़ा। पंचायत स्तर पर स्थिति और भी दिलचस्प है। 1990 के दशक में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हुआ, जिसके बाद देशभर में लगभग 14 लाख से अधिक महिलाएँ स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कई जगहों पर महिलाओं ने सरपंच और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में शिक्षा, जल-संसाधन और स्वास्थ्य से जुड़े निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संगीत और कला के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी दुनिया को नए ढंग से गढ़ा है। एक समय था जब सार्वजनिक मंचों पर महिलाओं का गाना या प्रदर्शन करना सामाजिक दृष्टि से सहज नहीं माना जाता था। उन्नीसवीं और बीसवीं सदी की शुरुआत में कई प्रतिभाशाली कलाकारों को केवल इसलिए संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वे महिलाएँ थीं। लेकिन इसी दौर में कुछ महिलाओं ने साहस के साथ परंपराओं को चुनौती दी। भारतीय शास्त्रीय संगीत में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, जिन्होंने अपनी साधना और प्रतिभा से न केवल कर्नाटक संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई बल्कि यह भी साबित किया कि एक महिला कलाकार की पहचान उसकी कला से बनती है, न कि सामाजिक सीमाओं से। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किशोरी अमोनकर और गिरिजा देवी जैसी गायिकाओं ने संगीत की परंपरा को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। फिल्म संगीत में लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। आज की पीढ़ी में श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान जैसी गायिकाएँ संगीत की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने के बाद यह दायरा और बढ़ा है। अब कई युवा महिला कलाकार स्वतंत्र रूप से अपना संगीत तैयार कर रही हैं और सीधे श्रोताओं तक पहुँचा रही हैं। यह परिवर्तन तकनीक और प्रतिभा के मेल से पैदा हुआ है, जिसने कला की दुनिया में महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले हैं।

सिनेमा और थियेटर की दुनिया में भी महिलाओं की भूमिका पहले से कहीं अधिक व्यापक हुई है। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में अधिकतर फिल्में पुरुष केंद्रित कहानियों पर आधारित होती थीं और पर्दे के पीछे काम करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। लेकिन समय के साथ यह स्थिति बदली है। अभिनेत्री से निर्देशक बनी अपर्णा सेन ने समानांतर सिनेमा में महिलाओं की संवेदनशील कहानियों को सामने लाने का काम किया। मीरा नायर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को नई पहचान दिलाई। हाल के वर्षों में ज़ोया अख्तर और मेघना गुलज़ार जैसी निर्देशकों ने मुख्यधारा के सिनेमा में मजबूत कहानियों के माध्यम से महिलाओं के अनुभवों को नए ढंग से प्रस्तुत किया है। अभिनय के क्षेत्र में भी स्मिता पाटिल और शबाना आज़मी जैसी अभिनेत्रियों ने समानांतर सिनेमा में महिला पात्रों को गहराई दी। आज की पीढ़ी में विद्या बालन और आलिया भट्ट जैसी अभिनेत्रियाँ ऐसे किरदार निभा रही हैं जो पारंपरिक रूढ़ियों को चुनौती देते हैं। थिएटर के क्षेत्र में भी उषा गांगुली और नीलम मानसिंह चौधरी जैसी रंगकर्मियों ने मंच को सामाजिक संवाद का माध्यम बनाया है। यह बदलाव केवल प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं है, बल्कि उन कहानियों का भी है जो अब समाज के सामने आ रही हैं।

विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियाँ इस बदलाव का सबसे प्रेरक उदाहरण हैं। कुछ दशक पहले तक वैज्ञानिक संस्थानों में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। 1950 और 1960 के दशक में भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दस प्रतिशत से भी कम था। लेकिन अब स्थिति धीरे-धीरे बदल रही है। अंतरिक्ष और विज्ञान की दुनिया में कई भारतीय महिलाओं ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इसरो के मंगलयान मिशन में वैज्ञानिक नंदिनी हरिनाथ और रितु करिधल जैसी महिलाओं ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं। टेसी थॉमस को भारत के मिसाइल कार्यक्रम में उनके योगदान के कारण ÷मिसाइल वुमन÷ कहा जाता है। जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किरण मजूमदार-शॉ ने उद्योग और विज्ञान के बीच एक नया पुल बनाया। इससे पहले भी भारत में वैज्ञानिक परंपरा में महिलाओं का योगदान रहा है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अन्ना मणि ने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। विज्ञान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी यह दिखाती है कि शिक्षा और अवसर मिलने पर प्रतिभा किसी सीमा को स्वीकार नहीं करती।

खेल के मैदान में महिलाओं की सफलता ने समाज की सोच को शायद सबसे तेज़ी से बदला है। कभी ऐसा माना जाता था कि खेल पुरुषों का क्षेत्र है, लेकिन आज भारतीय महिला खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही हैं। पी.टी. उषा ने 1980 के दशक में भारतीय एथलेटिक्स को नई पहचान दी। बाद में साइना नेहवाल और पी.वी. सिंधु ने बैडमिंटन में विश्व स्तर पर भारत की उपस्थिति मजबूत की। मुक्केबाज़ी में एम.सी. मैरी कॉम ने छह बार विश्व चैंपियन बनकर यह साबित किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद असाधारण उपलब्धियाँ हासिल की जा सकती हैं। कुश्ती में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने पारंपरिक सामाजिक ढाँचों को चुनौती दी। क्रिकेट में मिताली राज और हरमनप्रीत कौर जैसी खिलाड़ियों ने महिला क्रिकेट को नई लोकप्रियता दिलाई। खेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले दशक में महिला खिलाड़ियों को मिलने वाली सरकारी सहायता और प्रशिक्षण सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी और सफलता दोनों बढ़ी हैं।

स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत में मेडिकल शिक्षा के शुरुआती दौर में महिला डॉक्टरों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन आज स्थिति बदल रही है। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है। भारत की पहली महिला डॉक्टरों में आनंदीबाई जोशी का नाम इतिहास में दर्ज है, जिन्होंने उन्नीसवीं सदी में ही चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी थी। बाद में डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने न केवल चिकित्सा सेवा दी बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया। आज देशभर में लाखों महिला डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान यह साफ दिखाई दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने में महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। आशा कार्यकर्ताओं और नर्सों ने दूर-दराज़ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इन सब क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियाँ केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानियाँ नहीं हैं। यह सामाजिक परिवर्तन का संकेत हैं। शिक्षा के प्रसार, तकनीक के विस्तार और कानूनी सुधारों ने महिलाओं को नए अवसर दिए हैं, लेकिन असली बदलाव तब आया जब महिलाओं ने खुद अपने अधिकारों और संभावनाओं को पहचाना। पिछले तीन दशकों में महिला साक्षरता दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1991 की जनगणना में महिला साक्षरता दर लगभग 39 प्रतिशत थी, जो 2011 तक बढ़कर 65 प्रतिशत से अधिक हो गई। शिक्षा ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक निर्णयों में अधिक भागीदारी का अवसर दिया है।आज जब हम समाज में हो रहे बदलाव को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं ने अपनी दुनिया केवल बदली ही नहीं, बल्कि उसे नए अर्थ भी दिए हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि विकास का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होता है जब समाज का हर वर्ग उसमें सक्रिय रूप से भाग ले। राजनीति में नेतृत्व, विज्ञान में शोध, कला में रचनात्मकता और खेल में संघर्ष–इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति ने समाज को अधिक संतुलित और संवेदनशील बनाया है। महिलाओं ने यह इंतजार नहीं किया कि कोई और उनके लिए रास्ता बनाए। उन्होंने खुद रास्ते बनाए, अपने कदमों से उन्हें मजबूत किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए नई संभावनाएँ छोड़ीं। यही कारण है कि आज का भारत जब अपनी प्रगति की कहानी लिखता है, तो उसमें महिलाओं के संघर्ष, साहस और उपलब्धियों का अध्याय सबसे प्रेरक दिखाई देता है।

मंत्री श्री सारंग ने नरेला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिये निर्देश

शासकीय भूमि से अवैध कब्जे, मदरसे,

फैक्ट्री और मांस की दुकानें हटाने के निर्देश

भोपाल। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने शनिवार को नरेला विधानसभा के वार्ड क्रमांक 69, 70 और 71 का दौरा कर शासकीय भूमि से अवैध कब्जे, मदरसे, फैक्ट्री और मांस की दुकानें हटाने के निर्देश दिए। क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर मंत्री श्री सारंग स्वयं मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विस्तृत निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री सारंग ने शासकीय भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने नगर निगम, राजस्व, पुलिस सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध अतिक्रमण पर बने स्थानों को पेयजल, विद्युत सहित किसी भी प्रकार के शासकीय कनेक्शन न दिए जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि यदि ऐसे स्थानों को पहले से कनेक्शन दिए गए हैं तो उन्हें तत्काल हटाया जाए तथा यह जांच की जाए कि किन अधिकारियों की अनुमति से यह कनेक्शन दिए गए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंत्री श्री सारंग ने गुप्ता कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी और शहंशाह गार्डन, अशोका गार्डन क्षेत्र में पहुंचकर शासकीय भूमि की स्थिति का निरीक्षण किया और स्थानीय रहवासियों से भी चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना। निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि कई स्थानों पर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य किए गए हैं और कुछ जगहों पर बिना अनुमति के गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस पर मंत्री श्री सारंग ने मौके पर मौजूद नगर निगम, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे सभी अतिक्रमणों को चिन्हित कर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि शासकीय भूमि

जनता की संपत्ति है और उस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय भूमि पर अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसे, फैक्ट्री और मांस की दुकानों की विस्तृत जांच कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन कर शासकीय भूमि पर कब्जा किया है तो उसे तत्काल हटाया जाए और भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। मंत्री श्री सारंग ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में शासकीय भूमि का सर्वे कर विस्तृत सूची तैयार की जाए और जहां-जहां अतिक्रमण पाया जाए वहां चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर उसे हटाया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा न कर सके।

मंत्री श्री सारंग ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि नगर निगम, राजस्व और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय नागरिकों ने मंत्री श्री सारंग को कई स्थानों पर हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण की जानकारी दी। मंत्री श्री सारंग ने नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा और शासकीय भूमि को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नरेला विधानसभा क्षेत्र के विकास और नागरिकों की सुविधा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, अतिक्रमण या शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और निर्धारित समयसीमा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

महंगाई और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ जिला कांग्रेस भोपाल शहर का अनोखा प्रदर्शन

पीएम मोदी को दी 'डॉक्टर' की उपाधि

भोपाल। घरेलू एवं कमर्शियल गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर द्वारा आज रोशनपुरा चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना (अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर) के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं महिला कार्यकर्ता शामिल हुईं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक रूप से 'डॉक्टर' की उपाधि देते हुए विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार लगातार महंगाई का 'डोज' देकर आम जनता को परेशान कर रही है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 'महंगाई का इंजेक्शन' लिखे पोस्टर और तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शन में शामिल महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि घर की शुरुआत चूल्हे से होती है और गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। रसोई गैस आम परिवार की मूल आवश्यकता है, लेकिन इसकी कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी से गृहिणियों और मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने कहा कि वर्ष 2014 में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगभग ?400 के आसपास थी, जो अब बढ़कर करीब ?920 तक पहुंच गई है। हाल ही में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में लगभग ?60 तथा कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में करीब ?115 की वृद्धि की गई है, जिससे छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर ने चेतावनी दी है कि यदि गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जनहित में व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

इस अवसर पर प्रदेश प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा युवा कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष भोपाल अभिषेक शर्मा प्रदेश सचिव राजकुमार सिंह महिला कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव दीप्ति सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अभिनव बरोलिया समस्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गण पदाधिकारी गण, वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रायसेन के किले में अवैध हथियार बनाने पर सख्ती

कानूनगो का ट्वीट, महादेव मंदिर में पूजा करने से रोकने वालों को इस पर एक्शन लेना चाहिए

भोपाल (नप्र)। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने रायसेन के पुरात्तव विभाग के अधीन किले में अवैध हथियार बनाने, गोला बारूद चलाने, दहशत फैलाने, नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने और पुरातत्व धरोहर को नुकसान पहुंचाने के मामले में नोटिस देने का फैसला किया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि यहीं स्थित महादेव मंदिर में हिंदुओं को दर्शन करने से रोकने वाले स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इन अफसरों को इस मामले में जिम्मेदारों पर मुकदमा बना लेना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है, इसलिए आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। आयोग के सदस्य कानूनगो ने एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि मध्यप्रदेश के रायसेन में पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किले की सफील से आवासीय बस्ती के ऊपर देसी अवैध तोप चलाकर जनजीवन को खतरे में डाल रहे यह शोहदे ईरान और रमजान के नाम पर भय फैला रहे हैं। यहीं स्थित महादेव के मंदिर में हिंदुओं को दर्शन करने से बड़ी मुस्तैदी से रोकने वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा स्थानीय प्रशासन के अफसरों को उतनी ही तत्परता के साथ इन लफंगों पर मुकदमा करना चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य कानूनगो ने लिखा है कि बाकी हम तो कार्रवाई के लिए नोटिस भेज ही रहे हैं तब अफसरों को कर्तव्य पालन न करने का हिसाब भी देना होगा। उन्होंने एक्स पर वह वीडियो भी अपलोड किया है जिसके मामले में कार्यवाही नहीं की गई है। कानूनगो ने यह भी लिखा है कि नौकरी सरकार की है और नियम भी सरकार के हैं इसलिए पालन करवाना होगा। उन्होंने कहा है कि इन शोहदों ने इंस्टाग्राम पोस्ट में पुराने वीडियो भी सम्मिलित किए हैं जो एफआईआर लिखते वक्त ध्यान में रखना चाहिए।

मौत को मात देकर आई नन्हीं परी

खरगोन में 20 फीट गहरी पुलिया से गिरी गर्भवती महिला, कुछ ही देर बाद गूंजी किलकारी

खरगोन (नप्र)। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भगवानपुरा क्षेत्र के सिरवेल गांव के पास शुक्रवार को हुए एक सड़क हादसे में पुलिया से करीब 20 फीट नीचे गिरी गर्भवती महिला को राहगीरों ने बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। समय पर मिली मदद से महिला और नवजात दोनों सुरक्षित हैं।

अज्ञात बाइक सवार ने मारी टक्कर- जानकारी के अनुसार मोहराडी निवासी हीरालाल अपनी गर्भवती पत्नी और भाभी को मोटरसाइकिल से सिरवेल अस्पताल लेकर जा रहा था। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे सिरवेल में झूले के पास बनी पुलिया पर सामने से आ रही एक अज्ञात मोटरसाइकिल ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों सवार बाइक सहित पुलिया से नीचे जा गिरे।

ग्रामीणों की सहायता से पहुंचाया अस्पताल- हादसे में मोटरसाइकिल पुलिया के नीचे चट्टानों पर जा गिरी, जबकि तीनों लोग पानी भरे गड्ढे में गिर पड़े। घटनास्थल पर चारों ओर पत्थर और नुकीली चट्टानें होने के बावजूद तीनों की जान बच गई और उन्हें गंभीर चोट भी नहीं आई। इसी दौरान वहां से गुजर रहे सिरवेल निवासी समाजसेवी विक्रम ठाकुर और रमेश सोलंकी ने हादसे को देखा और तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद की। उन्होंने ग्रामीणों की सहायता से गर्भवती महिला को पुलिया के नीचे से ऊपर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद उमरिया पंचायत सचिव प्रवीण जायसवाल को मोबाइल पर घटना की जानकारी दी गई।

अस्पताल में दिया बच्ची को जन्म- सूचना मिलते ही प्रवीण जायसवाल ग्रामीण बाठिया कनासे के साथ चारपहिया वाहन से मौके पर पहुंचे। सभी की मदद से घायल दंपती और उनकी भाभी को सिरवेल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में भर्ती कराने के कुछ ही समय बाद गर्भवती महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। प्राथमिक उपचार के बाद मां और नवजात को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां दोनों का उपचार जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि समय पर मिली मदद से महिला और उसके बच्चे की जान बच सकी।

खाना परोस रहे होटल मालिक को साइलेंट अटैक

नर्मदापुरम में थाली में सब्जी रखते-रखते गिरा; भाई ने सीपीआर दिया, नहीं बची जान

नर्मदापुरम (नप्र)। नर्मदापुरम के ग्वालटोली रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल में गुरुवार रात एक व्यक्ति की साइलेंट अटैक से मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब वह होटल में ग्राहकों को खाना परोस रहे थे। अचानक वह थाली में सब्जी रखते-रखते नीचे गिर पड़े।

घटना का सीसीटीवी वीडियो शनिवार सुबह सामने आया। मृतक की पहचान अशोक नवलानी (60), निवासी सिंधी कॉलोनी गोकुलपुरी के रूप में हुई है। वह अपने भाई पप्पन नवलानी के साथ मिलकर होटल चलाता था।

वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही अशोक नवलानी नीचे गिरे, पहले तो आसपास मौजूद लोगों को समझ नहीं आया। कुछ ही पल बाद होटल के कर्मचारी और उनके भाई पप्पन नवलानी उन्हें उठाने के लिए दौड़े।

खंडवा के पुनासा में 90 वर्षीय बजुर्ग से खेत में गैंगरेप

कुएं में फेंकने का प्रयास किया, 12 घंटे तड़पती रही

खंडवा (नप्र)। जिले के पुनासा क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां खेत में अकेली रहने वाली 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ चार नकाबपोश बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। आरोपियों ने वृद्धा के मुंह में कपड़ा ठूंसकर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान महिला को इतनी गंभीर चोटें आईं कि उसका गुप्तांग फट गया और वह खून से लथपथ हालत में करीब 12 घंटे तक खेत में तड़पती रही। घटना के बाद आरोपी उसे कुएं में फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आसपास खेतों में लोगों की आवाजाही देखकर बदमाश उसे खेत में ही पटककर फरार हो गए।

खेत में अकेली रहती थी बुजुर्ग महिला- नर्मदानगर थाना प्रभारी विकास खींची ने बताया की पीड़ित बुजुर्ग महिला का खेत में ही एक छोटा सा घर है, जहां वह अकेली रहती है। महिला ने बताया कि गुरुवार रात खाना खाने के बाद वह सो गई थी। देर रात चार नकाबपोश बदमाश घर में घुस आए। आरोपियों ने पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह शोर न मचा सके।

लाड़ली बहना योजना ने बदली मंजू यादव की जिंदगी, सिलाई सेंटर खोलकर बनीं आत्मनिर्भर

● योजना से मिली सहायता से शुरू किया सिलाई का काम ● सिलाई केन्द्र में अन्य महिलाओं को भी दे रहीं रोजगार

भोपाल । कभी सीमित आय और जिम्मेदारियों के बीच अपने परिवार का सहारा बनने का सपना देखने वाली नर्मदापुरम की श्रीमती मंजू यादव आज आत्मनिर्भरता की नई पहचान बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से मिली आर्थिक सहायता ने न केवल उनके

जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाई, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी दिया।

नर्मदापुरम जिले के वार्ड क्रमांक 31 दीवान चौक ग्वालटोली निवासी 30 वर्षीय श्रीमती मंजू यादव को जून 2023 से योजना के अंतर्गत नियमित आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। इस राशि का उन्होंने सोच-समझकर उपयोग किया और अपने घर से सिलाई का छोटा-सा काम शुरू किया। मेहनत और लगन से शुरू किया गया यह प्रयास धीरे-धीरे एक सफल व्यवसाय में बदलने लगा। फरवरी 2026 तक उन्हें योजना की 33वीं किश्त सहित कुल 43 हजार 500 रुपये की सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। इस आर्थिक सहयोग और सिलाई कार्य से हुए मुनाफे का सदुपयोग करते हुए उन्होंने अपने काम का विस्तार किया और एक सिलाई सेंटर शुरू कर दिया, जिसमें अब पांच सिलाई मशीनें संचालित हो रही हैं। आज मंजू यादव न केवल स्वयं नियमित आय अर्जित कर रही हैं, बल्कि अपने सिलाई सेंटर के माध्यम से अन्य महिलाओं को भी रोजगार का अवसर प्रदान कर रही हैं। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और आत्मनिर्भरता की नई राह खुली है। श्रीमती मंजू यादव भावुक होकर कहती हैं कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना ने उनके जीवन में नया विश्वास जगाया है। इस योजना ने उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर दिया और आज वे गर्व के साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियों में योगदान दे रही हैं।

'न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी'

अदालत ने चेक अनादरित मामले में दोषी को सजा-मय ब्याज राशि भुगतान का दंडादेश पारित किया

सोहागपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेजदीपसिंह की अदालत ने वर्ष 2023 में भारतीय स्टेट बैंक एक व्यक्ति को लोन देने के बदले दिए गए चेक के अनादरित होने के मामले में आरोपी के विरुद्ध सजा मय ब्याज राशि भुगतान के दंडादेश का आदेश दिया है। इस मामले में बैंक पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं में वरिष्ठ अधिवक्ता जयप्रकाश माहेश्वरी, वकील सतीश नामदेव एवं वकील संदीप रघुवंशी ने इस प्रतिनिधि को बताया कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा पिपरिया रोड सोहागपुर में मेसर्स भाई वेल्डिंग वर्कशॉप के प्रोपराइटर इमरान खान पुत्र अयूब खान ने सीसी लिमिट लोन का आवेदन दिया था। जिसमें बैंक की शर्तों के अनुसार सात लाख रुपए का ऋण 17 मार्च 2023 को परिवादी बैंक ने स्वीकृत किया था। जिसमें आरोपी को ऋण राशि नियमित समयानुसार अदा करनी थी। लेकिन आरोपी ने बैंक से प्राप्त ऋण की प्रारंभ से ही समय पर अदायगी नहीं की। इस कारण आरोपी से परिवादी बैंक को सात लाख 30 हजार 911 रुपए एवं ब्याज लेना बाकी निकलता है। बैंक ने ऋण अदायगी के लिए परिवादी बैंक ने आरोपी से बार-बार निवेदन किया। इसके उपरांत आरोपी ने परिवादी बैंक को 24 नवंबर 2023 को केनरा बैंक सोहागपुर में स्वयं के खाते का 7 लाख 30 हजार 911 का एक चेक दिया। उक्त चेक परिवादी बैंक भारतीय स्टेट बैंक सोहागपुर में 28 सितंबर 2023 को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया। परिवादी बैंक प्रबंधक को 30 नवंबर 2023 को ज्ञात हुआ ।कि आरोपी के खाते में उक्त चेक राशि भुगतान के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। इसके

बावजूद जानबूझकर एवं बेईमानी पूर्वक परिवादी को धोखा देते हुए उक्त चेक आरोपी द्वारा प्रदान किया गया था। बैंक के अधिवक्ता जयप्रकाश माहेश्वरी ने कहा कि अभियुक्त का यह कार्य पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय श्रेणी में आता है। परिवादी बैंक ने 'आरोपी को 11 दिसंबर 2023 को पंजीकृत डाक से अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा था।जो 12 दिसंबर 2023 को आरोपी को प्राप्त हुआ। लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने 15 दिवस के अंदर परिवादी को चेक में वर्णित राशि अर्थात सात लाख 30 हजार 911 रुपये का भुगतान नहीं किया। इसके बाद शाखा प्रबंधक राघवेंद्र राजपूत ने तय समय सीमा में परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया । जिसमें विद्वान न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेजदीपसिंह ने अभियुक्त इमरान खान आत्मज अयूब खान निवासी किलापुरा वार्ड सोहागपुर को पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत सजा सुनाई है। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय ने छह माह के साधारण कारावास का दंडादेश एवं चेक की राशि सात लाख 30 हजार 911 रुपये पर एक लाख 49 हजार 106 रुपये ब्याज की राशि चुकाने का भी दंड सुनाया गया है। इस प्रकार अभियुक्त को परिवादी बैंक को आठ लाख 80 हजार 17 रुपये चुकाने होंगे। दंडादेश अनुसार अभियुक्त द्वारा यदि प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है ।ऐसी परिस्थिति में एक माह का साधारण कारावास भी भुगतना होगा। न्यायालय ने अभियुक्त को अभिरक्षा में लेते हुए सजा वारंट बनाकर पिपरिया उपजेल भेजने के निर्देश दिए हैं।

लौट रहे हैं अमिताभ महानायक का ऐलान

'कौन बनेगा करोड़पति' परदे पर वापस लौट रहा है। ये अचरज वाली बात इसलिए कही जा सकती है, कि जिस शो का अंत आशंका के साथ होता था, कि अगले सीजन में बतौर सूत्रधार अमिताभ लौटेंगे या नहीं! वही सीजन इस बार अपेक्षाकृत जल्दी शुरू होने की संभावना है। क्योंकि, इस शो की कल्पना अमिताभ बच्चन के बगैर नहीं की जा सकती। एक बार नए सूत्रधार का प्रयोग जरूर करने की कोशिश की गई, पर वो सफल नहीं हुआ।

महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर ज्ञान मंच पर कंटेस्टेंट की किस्मत संवारते नजर आएंगे। क्योंकि, टेलीविजन जगत का सबसे बड़ा रियलिटी शो अपनी अगली पारी के लिए तैयार है। 'देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं।' यह आवाज जल्द ही आपके घरों में फिर से गूंजने वाली है। देश के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का 18वां सीजन टीवी पर दस्तक देने के लिए तैयार है। सोनी टीवी के इस शो का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर आ चुका है, जिसमें अमिताभ बच्चन अपने पुराने अंदाज में शो की वापसी का ऐलान करते नजर आ रहे हैं।

प्रोमो की शुरुआत भी बेहद दिलचस्प अंदाज से होती है। अमिताभ बच्चन के मजेदार अंदाज में. कैमरा के सामने आकर कहते हैं 'सरप्राइज!' लाल रंग के वेलवेट कोट और ब्लैक ट्राउजर में वो हमेशा की तरह बेहद शानदार दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वे आईने के सामने खड़े होकर 'सरप्राइज' कहते हुए अपनी बाहें फैलाते हैं। हालांकि, बीच में वे अपनी एक छोटी सी गलती पर मुस्कुराते हुए 'सॉरी, गड़बड़ हो गई' भी कहते हैं और फिर अपना वीडियो आगे बढ़ाते हुए केबीसी के रजिस्ट्रेशन का ऐलान करते हैं।

केबीसी के 18वें सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी रजिस्ट्रेशन की तारीख। वीडियो में साफ तौर पर बताया गया है कि 9 मार्च से शो के सवाल और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दर्शक सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव ऐप के माध्यम से इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोमो के अंत में एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर भी दिया गया, जिसमें प्रतिभागियों को आगाह किया गया है कि वे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या लॉटरी के झांसे में न आएं। चैनल ने स्पष्ट किया है कि 'कौन बनेगा करोड़पति' कभी भी किसी से किसी भी प्रकार की फीस या शुल्क की मांग नहीं करता है।

अमिताभ बच्चन और केबीसी का नाता सालों पुराना है। पिछले सीजन के अंत में जब अमिताभ भावुक हुए थे। तब कई कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो वापस आएंगे। लेकिन, अब इस आधिकारिक प्रोमो ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। फैंस अपने चहेते होस्ट को फिर से हॉट सीट के सामने देखने के लिए बेताब हैं। जानकारी के मुताबिक ये नया सीजन जुलाई या अगस्त तक ऑन एयर होगा।

टिटहरी गीत पर बवाल बादशाह को नोटिस

मशहूर गायक और रैपर बादशाह एक बार फिर विवादों में आ गए। उनके नए हरियाणवी गीत 'टिटहरी' को लेकर हरियाणा महिला आयोग ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए उन्हें समन भेजा है। आयोग ने गायक को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में जारी हुए इस गीत के कुछ बोलों और दृश्य को लेकर आपत्ति जताई गई है। आयोग का कहना है कि इससे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचती है।

6 मार्च को जारी समन में बादशाह, जिनका असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है, को इस मामले में मुख्य पक्षकार बताया गया है। यह समन पानीपत के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जारी किया गया है। आयोग ने सुनवाई की तिथि 13 मार्च 2026 सुबह 11:30 बजे तय की है, जो पानीपत के उपायुक्त कार्यालय के सभागार में होगी।

गीत के बोलों के अलावा उसके दृश्य को लेकर भी आपत्ति दर्ज की गई है। वीडियो में स्कूल की वर्दी पहनी बच्चियों को दिखाए जाने पर आयोग ने सवाल उठाए हैं। आयोग का कहना है कि हरियाणवी संस्कृति और समाज से जुड़े गीतों में इस तरह की आपत्तिजनक भाषा और दृश्य नहीं होने चाहिए।

'ओह माय गॉड 3' से अलग हुई रानी मुखर्जी

अभिनेत्री रानी मुखर्जी और अभिनेता अक्षय कुमार को एक साथ फिल्म 'ओ माय गॉड 3' में देखने की चर्चा थी। लेकिन, अब खबर है कि रानी मुखर्जी इस परियोजना का हिस्सा नहीं रहेंगी। फिल्म में रानी मुखर्जी को मुख्य खलनायिका की भूमिका के लिए चुना गया था। जबकि, अक्षय कुमार इसमें पहले की तरह संक्षिप्त भूमिका में दिखाई देने वाले थे। अभिनेत्री को कहानी पसंद भी आई थी और आगे बातचीत होनी थी, लेकिन यह योजना प्रारंभिक चरण में ही रुक गई।

सूत्रों के मुताबिक अक्षय और रानी के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध हैं और दोनों साथ काम करने को लेकर उत्साहित भी थे। अब रानी के अलग होने के बाद निर्माता इस भूमिका के लिए नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग इसी वर्ष मई और जून में शुरू हो सकती है। रानी मुखर्जी हाल ही में फिल्म 'मर्दानी 3' में दिखाई दी थीं। इस फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया था और इसके निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं। फिल्म को प्रदर्शित होने के पहले दिन लगभग 4 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी।

रियल बॉक्स

फिर लौट आया सिनेमा का स्वर्णिम युग!

हेमंत पाल

लेखक 'सुबह सवेरे' इंदौर के स्थानीय संपादक है।

साल यानी 2025 में भारतीय फिल्मों का कुल ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 13,395 करोड़ रुपए तक पहुंचना अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह आंकड़ा महामारी से पहले के तीन वर्षों के औसत से 32% अधिक है, जो दर्शकों के व्यवहार में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है। लंबे समय तक घरों में बंद रहने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देखने के बाद जब दर्शकों को फिर से सिनेमाघरों में लौटने का अवसर मिला, तो उन्होंने इसे बड़े उत्साह के साथ अपनाया। तीसरी तिमाही में 4.05 करोड़ दर्शकों का सिनेमाघरों में पहुंचना और पिछले वर्ष की समान अवधि से 8.6% की वृद्धि यह स्पष्ट करती है कि थिएटर अब केवल मनोरंजन का विकल्प नहीं बल्कि सामाजिक अनुभव का केंद्र बन चुके हैं। इस सफलता के पीछे कई कारक काम कर रहे हैं। सबसे प्रमुख कारण मजबूत कंटेंट पाइपलाइन है। वर्ष 2025 में 100 करोड़ रुपए से अधिक कमाने वाली 37 फिल्मों का रिकॉर्ड बनना यह दर्शाता है कि निर्माताओं ने दर्शकों की पसंद को समझते हुए विविध विषयों पर फिल्में बनाई हैं। बड़े बजट की व्यावसायिक फिल्मों से लेकर छोटे बजट की कंटेंट-आधारित फिल्मों तक, दर्शकों को हर शैली और भाषा में विकल्प मिले। इससे सिनेमाघरों में लगातार भीड़ बनी रही और उद्योग को स्थिरता मिली।

मल्टीप्लेक्स उद्योग, विशेषकर पीवीआर आइनॉक्स जैसी कंपनियों ने इस उछाल का भरपूर लाभ उठाया है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 166.5% बढ़कर 95.7 करोड़ रुपए तक पहुंचना केवल वित्तीय सफलता नहीं बल्कि पूरे प्रदर्शन तंत्र की मजबूती का संकेत है। कंपनी की कुल आय में 9% की वृद्धि और 1,919.6 करोड़ रुपए का आंकड़ा बताता है कि सिनेमाघर केवल टिकट बिक्री पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि फूड एंड बेवरेज, प्रीमियम अनुभव और ब्रांड साझेदारियों के जरिए भी राजस्व बढ़ा रहे हैं। औसत टिकट की कीमत का 293 रुपए तक पहुंचना और प्रति व्यक्ति खान-पान खर्च का 146 रुपए तक बढ़ना दर्शकों की खर्च करने की क्षमता और उनकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। आज का दर्शक केवल फिल्म देखने नहीं, बल्कि एक पूरे अनुभव के लिए सिनेमाघर जाता है। बेहतर स्क्रीन, उन्नत ध्वनि तकनीक, आरामदायक सीटें और विविध खान-पान विकल्प उसके लिए महत्वपूर्ण हो गए। यही कारण है कि टिकट की कीमत में वृद्धि के बावजूद दर्शकों की संख्या में गिरावट नहीं आई, बल्कि वृद्धि दर्ज की गई है।

पीवीआर आईनॉक्स की रणनीति में छोटे शहरों और नए क्षेत्रों में विस्तार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 112 शहरों में 1,791 स्क्रीन का नेटवर्क यह दिखाता है कि सिनेमाघर अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहे। टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्क्रीन जोड़ने से नए दर्शक वर्ग तक पहुंच संभव हुई है। लेह और गंगटोक जैसे क्षेत्रों में विस्तार इस बात का संकेत है कि सिनेमा अब देश के हर कोने तक पहुंचने की क्षमता रखता है। दक्षिण भारत में 33% स्क्रीन का होना और उत्तर भारत में 27% स्क्रीन का वितरण क्षेत्रीय संतुलन को दर्शाता है। इस विस्तार का आर्थिक प्रभाव भी स्पष्ट है। मूवी एग्जीबिशन सेगमेंट से कमाई का चार गुना बढ़कर 159.3 करोड़ रुपए तक पहुंचना बताता है कि स्क्रीन बढ़ाने की रणनीति सफल रही है। साथ ही, वित्त लागत में 22.2 करोड़ रुपए की कमी और 27.1 करोड़ रुपए के टैक्स क्रेडिट ने कंपनी की लाभप्रदता को मजबूत किया है। यह संकेत देता है कि मल्टीप्लेक्स उद्योग अब केवल विस्तार नहीं बल्कि वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक स्थिरता पर भी ध्यान दे रहा है। क्षेत्रीय सिनेमा की भूमिका इस स्वर्णिम दौर में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 2025 में क्षेत्रीय फिल्मों का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6,488 करोड़ रुपए तक पहुंचना बताता है कि भारतीय दर्शक अब केवल हिंदी फिल्मों तक सीमित नहीं हैं। मलयालम फिल्मों का लगातार दूसरे वर्ष 1,000 करोड़ रुपए से अधिक कमाई करना यह दिखाता है कि क्षेत्रीय उद्योग गुणवत्ता और कहानी कहने के स्तर पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कन्नड़ सिनेमा की 74% और गुजराती सिनेमा की 188% वृद्धि यह साबित करती है कि स्थानीय कहानियां और सांस्कृतिक जुड़ाव दर्शकों को आकर्षित करने में अत्यंत प्रभावी हैं।

भारतीय सिनेमा के लिए साल 2025 सही मायनों में यादगार रहा। इस साल महामारी के बाद गुम हुई सिनेमा संस्कृति पूरी तरह लौट आई और बड़े बजट, दमदार कंटेंट व पैन-इंडिया अपील ने

बॉक्स ऑफिस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। साल के शुरू में 'छावा' ने दर्शकों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो साल के अंत में 'धुरंधर' की धमक ने दर्शकों को चमत्कृत कर दिया। इन एक्शन वाली फिल्मों से लगा कि दर्शक को ऐसी फ़िल्में ज्यादा पसंद आ रही है, तो यह भ्रम 'सैयारा' ने तोड़ दिया। इस प्रेम कहानी ने दर्शकों को मोहब्बत से सराबोर किया और आंखें भी गीली की। इस साल 'स्त्री-2' ऐसी फिल्म रही, जिसने कंटेंट की ताकत साबित की। हॉरर-कॉमेडी के सफल फॉर्मूले, मजबूत स्क्रिप्ट और राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर की जोड़ी ने दर्शकों को आकर्षित किया। छोटे बजट में बड़े मुनाफे ने इसे ट्रेड की पसंदीदा फिल्म बनाया। 'पुष्पा-2' ने भी कमाई का सिलसिला जारी रखा। अल्लू अर्जुन के स्टारडम, सशक्त एक्शन और बड़े पैमाने पर रिलीज रणनीति ने इसे सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल किया। एंटरटेनमेंट और यादगार डायलॉग इसकी ताकत बने। विजुअल ग्रैंड्योर और पौराणिक-साइंस फिक्शन मिश्रण से दर्शकों को 'कल्कि 2898 एड़ी' ने सिनेमाघरों तक खींचा। प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की मौजूदगी तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीक इसकी सफलता का आधार रही। इसके अलावा 'भूल भुलैया-3' जैसी कुछ मध्यम बजट की सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। क्योंकि, दर्शक अब कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा को प्राथमिकता दे रहे हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव के बावजूद सिनेमाघरों की लोकप्रियता का कारण यह भी है कि बड़े पर्दे का अनुभव अब भी अद्वितीय है। बड़े बजट की फिल्मों के दृश्य प्रभाव, ध्वनि और सामूहिक दर्शक प्रतिक्रिया को घर पर दोहराना कठिन है। इसके अलावा, मल्टीप्लेक्स कंपनियों ने प्रीमियम फॉर्मेट्स, विशेष स्क्रीनिंग और तकनीकी नवाचारों के जरिए सिनेमाघरों को आधुनिक बना दिया है। इससे युवा दर्शकों को आकर्षित करने में मदद मिली है। हालांकि, इस चमकदार तस्वीर के बीच कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। टिकट कीमतों में लगातार वृद्धि भविष्य में मध्यम वर्ग और छोटे शहरों के दर्शकों पर प्रभाव डाल सकती है। यदि कीमत बहुत अधिक बढ़ती हैं तो दर्शक फिर से डिजिटल विकल्पों की ओर झुक सकते हैं। इसके अलावा, कंटेंट की गुणवत्ता बनाए रखना भी उद्योग के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि दर्शक अब पहले से अधिक जागरूक और चयनात्मक हो चुके हैं। फिर भी, वर्तमान आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारतीय सिनेमा उद्योग ने महामारी के बाद न केवल खुद को पुनर्जीवित किया है बल्कि नए विकास मॉडल भी विकसित किए हैं। क्षेत्रीय भाषाओं का उदय, मल्टीप्लेक्स का विस्तार, प्रीमियम अनुभवों की मांग और विविध कंटेंट की उपलब्धता मिलकर एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं। निर्माता, वितरक और प्रदर्शक सभी अब डेटा-आधारित निर्णयों और दर्शक-केंद्रित रणनीतियों पर ध्यान दे रहे हैं।

भविष्य की दृष्टि से देखें तो उद्योग के सामने अपार संभावनाएं हैं। भारत की युवा आबादी, बढ़ती आय और शहरीकरण की प्रक्रिया सिनेमा के लिए दीर्घकालिक बाजार तैयार कर रही है। यदि कंपनियां छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती और सुलभ सिनेमाघर मॉडल विकसित करती हैं, तो दर्शकों का आधार और भी व्यापक हो सकता है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय फिल्मों की बढ़ती लोकप्रियता विदेशी राजस्व के नए अवसर खोल रही है। अंततः, वर्ष 2025 भारतीय सिनेमा के लिए केवल आर्थिक सफलता का वर्ष नहीं बल्कि आत्मविश्वास की वापसी का प्रतीक है। दर्शकों ने यह साबित कर दिया है कि सिनेमा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मजबूत कंटेंट, तकनीकी नवाचार और व्यापक विस्तार की रणनीतियों ने उद्योग को एक नए युग में प्रवेश कराया है। यदि यह गति बरकरार रहती है और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो आने वाले वर्षों में भारतीय सिनेमा न केवल घरेलू बाजार में बल्कि वैश्विक मंच पर भी और अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। यही कारण है कि वर्तमान दौर को सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जा रहा है, एक ऐसा समय जब परंपरा और आधुनिकता मिलकर मनोरंजन की दुनिया को नई दिशा दे रहे हैं।

- hemantpal60@gmail.com/ 9755499919

महिला दिवस विशेष

बिन नारी बेरंग है सिनेमा का रंग बिरंगा परदा

अशोक जोशी

आज की तरह हर साल महिला दिवस पर महिलाओं पर चर्चा होती है। लेकिन, फिल्मों में महिलाओं के योगदान पर ज्यादा बात नहीं होती। जबकि, हकीकत यह है कि हिंदी सिनेमा की विकास यात्रा में नारियों को उल्लेखनीय योगदान रहा है। नारी, सिनेमा का सबसे अनिवार्य और सशक्त घटक है। नारी के बिना सिनेमा भाव विहीन नजर आता है। जिन दिनों

सिनेमा का प्रादुर्भाव हुआ, सिनेमा में महिलाओं का काम करना प्रतिबंधित था। लेकिन, तब भी सिनेमा का परदा नारी विहीन नहीं हुआ। तब पुरुष कलाकार ही नारी का स्वांग रचकर दर्शकों को गुदगुदाया करते थे। लेकिन, जब परदे पर नायिकाओं का पर्दापण हुआ, नारी चरित्र सिनेमा में सशक्त आकार लेने लगे। आज जब सिनेमा सवा सौ साल से ज्यादा का सफर तय कर चुका है, नारी पात्र भारतीय सिनेमा की आत्मा बनकर उसमें समा गए हैं।

हिंदी सिनेमा मे वी शांताराम नारी समस्या को परदे पर सशक्त तरीके से उठाने वाले एक सशक्त फ़िल्मकार थे। उन्होंने प्रभात और राजकमल फिल्म निर्माण संस्थाओं के माध्यम से एक से एक बेजोड़ समाज सुधार की कलात्मक फिल्में बनाकर भारतीय सिनेमा मे नारियों के महत्व को प्रतिपादित किया। उनकी फिल्मों में 1937 में प्रदर्शित दुनिया न माने उल्लेखनीय है। बेमेल विवाह की समस्या पर आधारित यह फिल्म स्त्रीत्व की गरिमा को बेहद खूबसूरती से उभारती है। शांता आप्टे ने नायिका नीरा की भूमिका में प्राण फूंक दिए थे। नारी को को भोग्या, चरणों की दासी और उपभोक्ता-वस्तु मानने वालों को यह फिल्म करारा सबक सिखाती है। आज की इक्कीसवीं सदी की फिल्मों में भी यह जज्बा दिखाई नहीं देता।

1936 में निर्मित 'अछूत कन्या' ब्राह्मण लड़के और अछूत लड़की की एक दारुण प्रेम कहानी है। यह एक दुखांत फिल्म है। इस वर्जित और उपेक्षित विषय को पहली बार फिल्म के माध्यम से लोगों के बीच लाने का साहसिक प्रयास किया था। इससे मिलते जुलते विषय पर 1959 में विमल राय ने 'सुजाता' बनाई, जो फिर से अछूत लड़की और ब्राह्मण लड़के के प्रेम की कहानी है। विमल राय की यह फिल्म आज़ादी के बाद इस विषय पर बनाई गई पहली फिल्म थी। 'सुजाता' और उसके बाद हमारे देश में बहुत ही सशक्त सामाजिक सरोकार की फिल्में बनी, फिर भी हमारे यहां आज भी अंतर्जातीय और विधवा विवाह पूरी तरह मान्य नहीं हैं। राजकपूर और मीना कुमारी की ख्वाजा अब्बास निर्देशित फिल्म 'चार दिल चार राहें' भी इसी तरह समाज में नारियों की उपेक्षा की कहानी कहती है।

फिल्मों में नारी की स्थिति का चित्रण करने में बीआर चोपड़ा का उल्लेखनीय योगदान रहा। विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए उन्होंने 1958 में 'एक ही रास्ता' का निर्माण किया। उन्होंने साहस के साथ फिल्म में विधवा स्त्री का विवाह करवाकर सुधार की एक नई परंपरा को स्थापित किया था। अगले ही साल उन्होंने अविवाहित मातृत्व की समस्या से जूझने वाली स्त्रियों के जीवन के बिखराव और उसकी परिणति को दर्शाने वाली सशक्त फिल्म 'धूल का फूल' का निर्माण किया। ये फिल्में समाज को ऐसी विषम स्थितियों से बचने के लिए आगाह करती हैं और उन स्थितियों को बेबाकी से प्रस्तुत कर स्त्रियों के पक्ष में समाज को खड़े होने का साहस प्रदान करती हैं। बीआर चोपड़ा अपनी एक और फिल्म 'इंसाफ का तराजू' में

बलात्कार से पीड़ित लडकी को न्याय दिलाते हैं। इस विषय पर बहुत कम फिल्में बनी, इसलिए इसे एक नई साहसपूर्ण प्रस्तुति के रूप में स्वीकार किया गया। 'निकाह' में उन्होंने तलाक और हलाला जैसे विषयों को छूने का प्रयास किया तो उन्हीं की फिल्म 'साधना' समाज में वेश्याओं की स्थिति पर प्रकाश डालने में सफल रहीं।

अपने शैशव काल से ही हिंदी फिल्में स्त्री प्रधान रहीं हैं। हिंदी फ़िल्मकारों ने भारतीय स्त्री के सभी रूपों को फिल्मों में प्रस्तुत किया है। घरेलू स्त्री, कामकाजी स्त्री, किसान स्त्री, विवाहित और अविवाहित स्त्री आदि। जुझारू स्त्री, संघर्षशील स्त्री और अन्याय और अत्याचार से लड़ने वाली स्त्री आदि रूप हिंदी फिल्मों में प्रमुख रूप से आते रहे हैं। महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म 'औरत' और उसका संशोधित संस्करण 'मदर इंडिया' भारतीय किसान नारी के संघर्ष और त्रासदी की महागाथा है। जिसमें ग्रामीण महाजनी सभ्यता की क्रूरता और अत्याचार से लड़ती हुई नारी की मार्मिक कहानी भी है। जमींदारी अन्याय से लड़ते लड़ते गांवों में डाकुओं की जमात भी तैयार होती है। ग्रामीण सामंती अत्याचार से उत्पन्न डाकू समस्या को उजागर करने वाली फिल्मों में नारी की विवशता को मुझे जीने दो, गंगा जमुना, जिस देश में गंगा बहती है और शेखर कपूर की 'बैंडिट क्वीन' में पूरी विश्वसनीयता के साथ परदे पर उतारा गया।

राज कपूर द्वारा निर्मित 'प्रेम रोग' में अभिजात्य परिवार की विधवा युवती का विवाह सामान्य वर्ग के युवक से करवाकर सामाजिक विषमता को मिटाने की पहल की गई। 'राम तेरी गंगा मैली' में भी राज कपूर ने नारी व्यथा को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। इसी श्रेणी में राजीव कपूर निर्देशित 'प्रेमग्रंथ' भी आती है जो कि यौन शोषण से उत्पीड़ित नारी को काठ की हांडी के रूप में प्रस्तुत करती है। इस फिल्म के माध्यम से ऐसी लांछित स्त्रियों को समाज में स्वीकार करने की पहल की गई। कुछ इसी तरह की फिल्म थी राज कुमार संतोषी की 'लज्जा' जिसमें समाज के अलग-अलग परिवेशों से आने वाली तीन शोषित स्त्री पात्रों के दारुण शोषण और मुक्ति के संघर्ष को दर्शाया गया है। राजकुमार संतोषी की फिल्म 'दामिनी' में भी बलात्कार से पीड़ित घर की एक नौकरानी को न्याय दिलाने की कहानी को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया था।

श्याम बेनेगल की पहली फिल्म 'अंकुर' भी अछूत औरत और ब्राह्मण आदमी के रिश्ते की कहानी है। इसके बाद, भुवन शोम, मृगया, भूमिका, मंडी, चक्र आदि फिल्मों में श्याम बेनेगल ने हाशिये पर पड़ी नारियों की सामाजिक स्थिति की दर्दमय झांकी प्रस्तुत की। प्रकाश झा भी नारी विषय पर फिल्में बनाने में माहिर है। उनकी फिल्म 'दामुल' में अमीर लोगों द्वारा गरीबों का शोषण दिखाया गया। इसके बाद 'मृत्युदंड' में उन्होंने ग्रामीण वातावरण में स्त्री के यौन शोषण और कर्मकाण्डी धार्मिक व्यवस्था द्वारा स्त्री की दुर्गति के प्रयासों के विरुद्ध स्त्रियों के संघर्ष को दर्शाया गया। यहां 'खून भरी मांग, दीवार और स्मिता पाटिल की 'वारिस' की चर्चा करना भी प्रासंगिक होगा जिसमें महिलाओं की महिमा को शिद्दत के साथ प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा क्वीन, गुलाबी गैंग, इंग्लिश-विंग्लिश, पिंक, दंगल, छपाक, थप्पड़, कहानी, मर्दानी, सीता और गीता, लापता लेडीज, दामिनी, गुंजन सक्सेना, नीरजा, और गंगूबाई काठियावाड़ी में भी महिलाओं से संबंधित विषयों को छुआ है।

सिनेमा में नारी व्यथा और उनकी दयनीय स्थिति को उजागर करने वाली फिल्मों उनके निर्माताओं के योगदान को स्मरण करना महत्वपूर्ण है। उतना ही परदे पर नारी दशा को प्रकट करने वाली अभिनेत्रियों में शांता आप्टे से लेकर नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला, नूतन, वहीदा रहमान, जया बच्चन, हेमा मालिनी, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, राखी, रेखा, डिम्पल कपाड़िया, जीनत अमान, माधुरी दीक्षित मीनाक्षी शेषाद्री, कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, और आलिया भट्ट सहित सभी नायिकाओं और सहनायिकाओ के योगदान को स्मरण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा।

मिट्टी, बीज और उम्मीद: महिलाओं के हाथों उगता नया संसार

विश्व महिला दिवस पर विशेष

कुमार सिद्धार्थ
लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

सुबह की पहली किरण जब धरती को सहलाती है, तो वह केवल उजाला ही नहीं लाती वह उन अनगिनत स्त्रियों की मौन आस्था भी साथ लाती है, जो अपने श्रम, संवेदना और धैर्य से प्रकृति को फिर से जीवन दे रही हैं। देश के परिदृश्य में देखें तो पाएंगे कि वे बुंदेलखंड की प्यास से फटी धरती पर सूखे तालाबों में पानी की स्मृतियाँ लौटा रही हैं; तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के जंगलों में वे बीजों को ऐसे सहेजती हैं जैसे माँ अपने शिशु को; और उत्तराखंड की पहाड़ियों पर वे पेड़ों की रखवाली करती हुई मानो भविष्य की पहरेदार बन जाती हैं। ये स्त्रियाँ पर्यावरण को नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता को बचा रही हैं।

इसी व्यापक सोच और जीवनानुभव से जन्मी इस चेतना को दुनिया ÷इकोफेमिनिज़्म÷ कहती है यानी पर्यावरण नारीवाद, एक ऐसा नजरिया जो प्रकृति और स्त्री की मुक्ति को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ मानता है। यह विचार बताता है कि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, वैसे ही समाज में महिलाओं के श्रम और अधिकारों का भी शोषण होता है। जब जलस्रोत सूखते हैं, जंगल कटते हैं या भूमि बंजर होती है, तो सबसे पहले इसका असर महिलाओं पर पड़ता है उन्हें पानी के लिए दूर तक चलना पड़ता है, ईंधन और चारे के लिए अधिक श्रम करना पड़ता है। यही अनुभव उन्हें पर्यावरण संरक्षण का स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता बना देता है, क्योंकि उनके लिए प्रकृति कोई संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार, सहचर और भविष्य की आशा है।

यह विचार किसी सिद्धांत की उपज नहीं, बल्कि पीढ़ियों से संचित जीवनानुभव की देन है। भारतीय ग्रामीण और आदिवासी समाज में यह भावना सदियों से रची-बसी है, जहाँ धरती को माँ और प्रकृति को पालनहार माना जाता है। यही कारण है कि जब महिलाएँ पर्यावरण संरक्षण की पहल करती हैं, तो वह केवल हरित अभियान नहीं रहता वह सामाजिक परिवर्तन की एक शांत किंतु सशक्त प्रक्रिया बन जाता है। जो महिलाएँ कभी निर्णयों की चौखट से दूर रखी जाती थीं, वही आज ग्रामसभाओं में योजनाएँ बना रही हैं, सामुदायिक बैठकों में दिशा तय कर रही हैं और अपने गाँव के भविष्य की रूपरेखा स्वयं लिख रही हैं।

ग्रामीण जीवन में महिलाएँ पानी लाने, चारा जुटाने, लकड़ी इकट्ठा करने और खेती करने जैसे कार्यों के कारण प्रकृति से प्रत्यक्ष जुड़ी रहती हैं। पर्यावरण चिंतक डॉ. वंदना शिवा ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि आधुनिक विकास मॉडल ने प्रकृति और स्त्री दोनों को ÷संसाधन÷ मानकर उनका उपयोग किया, जबकि पारंपरिक समाज उन्हें जीवन के आधार के रूप में देखता था। इसी सोच को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने नर्मदा घाटी आंदोलन में जीवंत रूप दिया, जहाँ नदी, विस्थापन और महिलाओं के अधिकार जैसे तीनों प्रश्न एक साथ उठाए। वहीं इंदौर की पद्मश्री जनक मिलिगियन पलटा ने सौर उर्जा के माध्?यम से सैकडों आदिवासी युवतियों के जीवन को रोशन करने का प्रयास किया है। पर्यावरण विद सुनीता नारायण ने दुनिया में कार्बन उर्त्?सजन में कमी लाने के लिए सरकारों के साथ मिलकर नीतिगत मसलों पर काम किया है।

महिला नेतृत्?वकर्ताओं ने देश के अनेक राज्यों में स्वयं सहायता समूहों के माध्?यम से जैविक खेती, रसोई बाग़, वर्मी कम्पोस्ट और वनौषधि उत्पादन जैसी पहलें शुरू की हैं। इन पहलों से न केवल महिलाओं की आय बढ़ी है, बल्कि रासायनिक खेती पर निर्भरता भी घटी है। मध्य भारत के कई क्षेत्रों में सामुदायिक खेती की परंपरा फिर से जीवित हो रही है, जहाँ पारंपरिक बीजों और प्राकृतिक तरीकों से खेती की जाती है। इसका परिणाम केवल उपज नहीं, बल्कि मिट्टी की सेहत, परिवारों का पोषण और महिलाओं का आत्मविश्वास है याने एक साथ तीनों का विकास।

इतिहास भी इस चेतना का साक्षी है। राजस्थान की मरुभूमि में सदियों पहले एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने प्रकृति-प्रेम को आस्था का स्वर दे दिया। 1730 में जोधपुर रियासत के खेजड़ली गाँव में अमृता देवी विश्नोई ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। जब शाही सैनिक खेजड़ी वृक्ष काटने पहुँचे, तो उन्होंने पेड़ से लिपटते हुए कहा ÷सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाण÷ याने यदि पेड़ बचाने में सिर भी कट जाए तो यह सौदा सस्ता है। उनके साथ 363 विश्नोई स्त्री-पुरुषों ने बलिदान दिया। विश्नोई समाज की जीवन पद्धति प्रकृति के साथ सहअस्तित्व की मिसाल है; वे पेड़ों को परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं, वन्यजीवों को अपना साथी समझते हैं और पर्यावरण संरक्षण को धर्म मानते हैं। यह घटना केवल इतिहास नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है जिसमें स्त्री, प्रकृति और जीवन एक ही सूत्र में जुड़े हैं। अमृता देवी का बलिदान मानो समय की रेत पर लिखा वह संदेश है जो आज भी हर हरित पहल को प्रेरित करता है कि धरती की रक्षा केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जीवन का सबसे पवित्र संकल्प है।

1970 के दशक में उत्तराखंड की ग्रामीण महिला गौरा देवी और उनकी साथिनों ने पेड़ों से लिपटकर जंगल कटाई रोक दी। यही घटना आगे चलकर ÷चिपको आंदोलन÷ के नाम से विश्वभर में प्रसिद्ध हुई और इसने सिद्ध कर दिया कि पर्यावरण संरक्षण स्त्री जीवन से कितना गहरे जुड़ा है।

जमीनी स्तर पर सक्रिय महिला संगठन- भारत में कई महिला-केंद्रित संगठन पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण को साथ जोड़कर काम कर रहे हैं। ग्रामीण भारत में पीढ़ियों से महिलाएँ मौसम, मिट्टी और औषधीय पौधों का पारंपरिक ज्ञान संजोती आई हैं। अब कई संस्थाएँ इस ज्ञान को दस्तावेज़ित कर रही हैं और युवा पीढ़ी तक पहुँचा रही हैं। गाँवों में पर्यावरण पाठशालाएँ, महिला प्रशिक्षण शिविर और सामुदायिक संवाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। सेवा (SEWA) वर्षों से हजारों महिलाओं को हरित आजीविका जैविक खेती, हस्तशिल्प और टिकाऊ उत्पादन से जोड़कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना रहा है। मध्य भारत में सक्रिय दीक्षा महिला समूह सामुदायिक खेती और बीज संरक्षण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। झारखंड-छत्तीसगढ़ क्षेत्र में वनाधिकार महिला मंच आदिवासी महिलाओं को वनाधिकार, जल प्रबंधन और बीज बचाओ अभियानों से जोड़कर उनके नेतृत्व को सशक्त कर रहा है, जबकि राजस्थान में स्थानीय नेटवर्क के रूप में कार्यरत ग्रीन बेल्ट महिला समूह पौधरोपण, जल संरक्षण और चारागाह पुनर्जीवन जैसे कार्यों से रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली की नई कहानियाँ लिख रहा है। ये पहलें प्रमाण हैं कि जब महिलाएँ संगठित होती हैं, तो पर्यावरणीय और सामाजिक परिवर्तन की गति कई गुना बढ़ जाती है।

झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अनेक गाँवों में महिलाएँ सामुदायिक बीज बैंक चला रही हैं। उनके लिए बीज केवल खेती का साधन नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र की किसान लक्ष्मी हिड़का और उनका समूह चालीस से अधिक पारंपरिक धान किस्मों को संरक्षित कर रहा है। उनका विश्वास सरल लेकिन गहरा है जब बीज हमारे पास होता है, तो खेती भी हमारे हाथ में होती है।

इसी तरह बुंदेलखंड और मराठवाड़ा जैसे सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में महिलाएँ जल संरक्षण अभियानों की अगुवाई कर रही हैं। वे पुराने तालाबों की सफाई, वर्षा जल संचयन और मिट्टी संरक्षण के कार्य कर रही हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले में कमला देवी चौधरी के नेतृत्व में तीस महिलाओं ने तीन वर्षों में पाँच सौ से अधिक पौधे लगाए और जल संरचनाएँ बनाईं। परिणाम यह हुआ कि गाँव का तापमान घटा, नमी बढ़ी और पानी टिकने लगा मानो धरती ने राहत की साँस ली हो।

स्वावलंबन से सामाजिक बदलाव- ज्ञान की परंपरा भी इन स्त्रियों के हाथों सुरक्षित है। ग्रामीण समाज में महिलाएँ औषधीय पौधों, मौसम और मिट्टी के स्वभाव का गहरा ज्ञान रखती हैं। तेलंगाना की डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी और नवदान्य जैसे नेटवर्क इस पारंपरिक ज्ञान को दस्तावेज़ित कर नई पीढ़ी तक पहुँचा रहे हैं। इन पहलों में महिलाएँ स्वयं प्रशिक्षक बनकर खेती, पोषण, बीज संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा सिखाती हैं ज्ञान का यह साझा होना ही असली सशक्तिकरण है।

आर्थिक आत्मनिर्भरता इस बदलाव की धुरी है। जैविक खेती, मधुमक्खी पालन, वर्मी कम्पोस्ट और वनौषधि उत्पादन जैसी गतिविधियों से महिलाएँ स्थानीय बाज़ारों में सीधे अपने उत्पाद बेच रही हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में यह परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है जहाँ आय के साथ-साथ निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ी है और महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा मजबूत हुई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि टिकाऊ विकास की नीतियाँ तभी सफल होंगी जब उनमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हो। पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति इस दिशा में सकारात्मक संकेत है। देश में कुछ महिला संगठन लंबे समय से हरित विकास के लिए अपना योगदान दे रहे है।

हालाँकि चुनौतियाँ अब भी कम नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन, खनन परियोजनाएँ, भूमि अधिग्रहण और सामाजिक रूढ़ियाँ कई बार इन प्रयासों की राह में बाधा बनती हैं। पर्यावरणीय निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है, संसाधनों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। फिर भी छोटे-छोटे स्थानीय प्रयास यह विश्वास दिलाते हैं कि परिवर्तन नीचे से शुरू होकर ऊपर तक पहुँच सकता है।

भविष्य की राह-सहअस्तित्व का दर्शन- पर्यावरण नारीवाद का मूल संदेश यही है कि पर्यावरण संरक्षण कोई तकनीकी योजना भर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का प्रश्न है। जब महिलाएँ प्रकृति की रक्षा करती हैं, तो वे दरअसल अपने जीवन, अपने अधिकार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा कर रही होती हैं। भारतीय परंपरा में धरती को माँ कहा गया है और शायद यही भाव इस पूरे आंदोलन की आत्मा है। धरती और स्त्री दोनों सृजन का स्रोत हैं; यदि दोनों को सम्मान और सुरक्षा मिले, तो विकास भी संतुलित, टिकाऊ और मानवीय होगा।

भारत के गाँवों में उभरती ये छोटी-छोटी हरित कहानियाँ आने वाले समय में एक विराट वन का रूप ले सकती हैं ऐसा वन जहाँ विकास, समानता और प्रकृति साथ-साथ फलें-फूलें। यही इस युग की सबसे सुंदर संभावना है साझेदारी का भविष्य, बगैर शोषण का।

...और क्या कह रही है ज़िंदगी

ममता तिवारी
लेखिका साहित्यकार हैं।

महिला दिवस: इक ख़त, खुद के नाम

प्रिय स्त्री,

बहुत सालों से इसी इंतज़ार में बिता दिए कि तुम्हें ख़त लिखकर अनकही बातें लिख कर बता दूँ। उम्र के महत्वपूर्ण पायदान में कदम रखने वाली हो। अब तुम में बहुत धैर्य, शांति से समझने की, चिंतन की, चिंता की नहीं, सहन करने की शक्ति आ गई है तो थोड़ा बेबाकी से लिख पा रही हूँ। बचपन से ही शुरू करती हूँ। तुम्हारा बचपन बहुत खूबसूरत था, छोटी होने के नाते लाड़ली भी थी, पर जिद्दी नहीं थी। पढ़ने में होशियार, हर क्षेत्र में अव्वल रहने वाली तुम मुझे बहुत प्रिय थीं। अपनी कलाओं से, बुद्धिमता से सबको प्रभावित कर लेती थी पर ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ तुम्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था तो माँ से तुमने पेटदर्द का खूब बहाना बनाया, बेचारी तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर जाती थीं।

एक खिलंदडी, खुशमिज़ाज लड़की थी तुम। बातों को देर तक मन में नहीं रखती थी और अब? बड़ा अफ़सोस होता है बचपन में तुमने अपनी काफी ऊर्जा रंग गोरा करने में, सुंदर दिखने में लगाई। तुम्हारी ढेरों किताबें पढ़ने की आदत मुझे पसंद थी। युवावस्था में सुंदर दिखने का जुनून तुमने छोड़ दिया। अब तुम किताबों, पढ़ाई की दीवानी हो गई। मुझे अच्छा लगा था। पर फिर भी मैंनें देखा तुम भीड़ में जाने से कतराती थीं। तुम्हें स्टेज फीयर था पर तुम अपने आप को मजबूत दिखाती थीं, सच है ना। शादी के बाद तुम्हारी कमज़ोरी पे मुझे बहुत गुस्सा आया, सब के कहने पर जॉब छोड दिया। भावनायें दबाने से तुम थोड़ी जिद्दी हो गईं। तुम कुछ कह नहीं पाती थी तो तुमने रो-रोकर को प्रताड़ना दी, स्वास्थ्य का खयाल नहीं रखा, की वजह से हमेशा चिड़चिड़ाती थीं, बीमार रहती थीं। तुम्हारे बड़े बच्चे पर इसका बहुत असर पड़ा वो अंर्तमुखी हो गया था। हर बात पर रोती थी। तुम ! काश! उस वक्त तुमने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती। दूसरे बच्चे तक तुम थोड़ी शांत, धैर्यवान, सहनशील हो गई थी जिससे उसका बचपन अच्छा रहा। तुमने सिर्फ एक ज़िद के लिये कि किसी ने कहा नौकरी पेशा बहू घर अच्छे से नहीं संभाल सकती ये बात दिल से लगा ली अब तुमने खुद को साबित करने में पूरी ऊर्जा लगा दी पर तुम उन लोगों को खुश करने में लगी थी, जो तुमसे संतुष्ट नहीं थे। तुमने अपने प्रति हुये अन्यायों पर आवाज़ नहीं उठाई पर बागीपन तुम्हारी कलम में आ गया था। बच्चों को तुमने बहुत अच्छी परवरिश दी तुम माँ के रूप में या श्दोस्त के रूप में सफल रही।

तुमने खुद को आंकने का अधिकार उन हाथों में दे दिया जिन्हें तुम्हारी ज़रा कदर नहीं थी। मैं बहुत नाराज़ थी तुमने बहुत शक्ति जाया की। ना तुम उन्हें खुश रख पाईं ना खुद खुश रहीं। 35 से 58 बरस तक तुम्हारा सुनहरा काल था जब तुमने खुद को, गढ़ा, पुनः जन्मा, आत्मविश्वासी बनी और एक अच्छी लेखिका, समाज सेवी बनी। तुम्हारे आत्म विश्वास ने तुम्हे भीतर बाहर से खूबसूरत बना दिया। आज तुम अपने निर्णय खुद लेती हो। पर देख रही हूँ तुम अब उम्र और अकेलेपन की

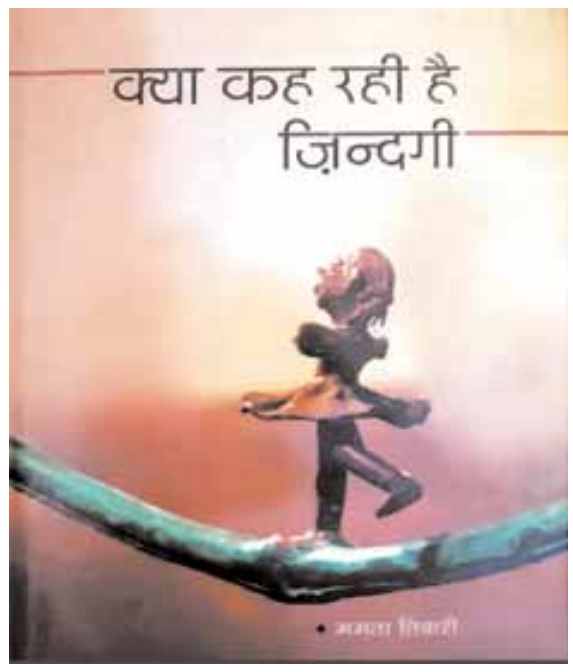

वजह से डरपोक भी हो रही हो। बच्चों को ये बात अब पसंद नहीं। तुम्हें फिर खड़े होना होगा जो मकाम पाया है, उसे साधना होगा, तुम्हें खुद का खयाल रखना होना, खुद के साथ रहना सीखना होगा।

तुम्हें अकेले आनंदित होने की आदत डालनी होगी। अपने सिद्धांतों और सच्चाई कहने की आदत को कम करना होगा क्योंकि सब कड़वा सच बर्दाश्त नहीं कर पाते, तर्क करना तुमने छोड़ दिया अच्छा है। उसमें तुमने बहुत ताकत बरबाद की। मुँह फट होना, हाज़िर जवाब होने में अब तुम्हें फर्क समझ आ गया है। जहाँ तुम सहमत नहीं हो, करवा भी नहीं पाती हो तो विषय बदल दो। भावुकता में बहकर तुमने घर के कोने-कोने से लेकर इंसानों से प्यार और विश्वास किया, धोखा खाया, ये आदत अब भी है तुम मैं मैं ये नहीं कहती ये गलत है, पर आजकल के ज़मानें में थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है क्योंकि फिर तुम्हें प्यार के बदले प्यार और विश्वास के बदले विश्वास की उम्मीद नहीं करना चाहिये। तो ये थी तुम्हारी कुछ कमियाँ और अच्छाई। उम्र ने तुम्हारी बैचेन तबीयत को थोड़ा संतुलित कर दिया है। पर बेवज़ह ब्लड प्रेशर बढ़ाना और रातों को जागना छोड़ना होगा। सब अपने हिस्से की धूप और अंधकार ले के आये है, तुम दूसरों की जिंदगी में उजाला कर रही हो अच्छा लगता है पर पूरी तरह उसमें घुस जाना बहुत गलत है। मन ही मन दूसरों के झूठ और गलत व्यवहार पे दुःखी होने की जगह उन्हीं के बीच अपने सिद्धांतों के साथ रहना होगा। तुम्हें ख़ामोशी को मौन में बदलना होगा थोड़ा ध्यान पे काम और करना होगा। जो तुमसे कांउसिलिंग की उम्मीद करते हैं उनकी मदद करो पर एक सीमा रेखा खींचनी होगी। इस तरह तुमने बहुत लोगों से दूरी बनाई, पर हम अपने मुताबिक दुनियाँ नहीं बना सकते। कुदरत ने भी किसी को झूठा बेईमान, धोखेबाज़ बना के नहीं भेजा था, वो तो परिस्थितिवश ऐसे हो गये। तो खुद की बेहतरी के लिये अपने को बदलो और मैंनें देखा तुमने ये अब सीख लिया है। तो दूसरों से पहले स्वयं की परवाह करना होगा....

कभी-कभी बातूनी स्त्री अपने आप को ख़ामोश कर एक गुफा में बंद कर लेती है, क्योंकि वो किसी से उलझना नहीं चाहती। ये उसका पलायन नहीं चिंतन है।

मैं भला वापस कैसे आती ?
जब मैं कहीं गई नहीं थी
हाँ गई तो थी उम्रदराज़ होने
होने थोड़ी परिपक्व, तजुर्बा बटोरने
समय की भट्टी में थोड़ा तपने
ताकि थोड़ा और निखर जाऊँ
पर अबकी बात भीतर से संवरनें की थी
बाहर से कठोर, अंदर से मोम होने की थी
चिंतन की थी
चिंता की नहीं
दौड़ने की नहीं
ख़रामा ख़रामा चलने की थी
हम जाते कहीं नहीं, क्रेरेंटाइन हो जाते हैं
और इंतज़ार करते हैं, इम्युन बढ़ने का
फिर तैयार हो जाते हैं नये अनुभव के साथ
जीवन संग्राम में लड़ने के लिये मशाल लिये
तो चलते रहो, जलते रहो।

... और पूछते रहो अपनी मित्रों से और क्या कह रही है जिंदगी।

नारी शक्ति की नई उड़ान: परंपरा, तकनीक और बदलती दिशा

संगीता शर्मा
(मप्र राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य एवं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता)

हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि यह समाज को यह सोचने का अवसर देता है कि महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकार और उनकी संभावनाएँ किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक मापदंड उसकी आधी आबादी यानी महिलाओं की स्थिति से तय होता है।

भारतीय समाज में नारी को सदैव सम्मान का स्थान दिया गया है। समय के साथ महिलाओं की भूमिका भी निरंतर विकसित हुई है। आज महिलाएँ केवल परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन और उद्यमिता जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बराबरी की भागीदारी निभा रही हैं।

वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि नई पीढ़ी की युवतियाँ–जिन्हें आज की भाषा में जेनरेशन - जी (Generation Z)(पीढ़ी परिवर्तक) कहा जाता है–समाज में बदलाव की नई धारा लेकर सामने आ रही हैं। यह पीढ़ी अधिक जागरूक, आत्मविश्वासी और तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलने वाली है। आज की युवतियाँ अपने करियर, शिक्षा और जीवन के निर्णय स्वयं लेने के प्रति अधिक सजग और स्वतंत्र सोच रखती हैं। वे सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देते हुए नए अवसरों की ओर अग्रसर हो रही हैं।

इसी के साथ तकनीक का तेजी से बढ़ता प्रभाव भी महिलाओं के लिए नए द्वार खोल रहा है। विशेष रूप से rtificial Intelligence (AI) आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी आधुनिक तकनीकों ने शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में नई संभावनाएँ पैदा की हैं। आज महिलाएँ डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप, ऑनलाइन शिक्षा और तकनीकी नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई मिसालें स्थापित कर रही हैं। यदि सही प्रशिक्षण और अवसर मिलें, तो यह तकनीकी क्रांति महिलाओं को सशक्त बनाने का एक बड़ा माध्यम बन सकती है।

हालांकि इन सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद समाज में कई चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। महिलाओं के प्रति भेदभाव, असुरक्षा की भावना और अवसरों में असमानता आज भी कई स्थानों पर देखने को मिलती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसरों को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

ऐसी स्थिति में महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं, बल्कि समाज की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। जब एक महिला शिक्षित, आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम होती है, तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार और समाज की दिशा बदल देता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम महिलाओं को समान अवसर, सुरक्षित वातावरण और आधुनिक तकनीक से जुड़ने के अधिक अवसर प्रदान करें। जब बेटियों को शिक्षा, युवतियों को अवसर और महिलाओं को सम्मान मिलेगा, तभी एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव होगा।

नारी केवल संवेदना और त्याग की प्रतीक नहीं है, बल्कि साहस, नेतृत्व और परिवर्तन की शक्ति भी है। नई पीढ़ी की जागरूक युवतियाँ और आधुनिक तकनीक का समन्वय आने वाले समय में समाज को एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है। इसलिए हमें महिलाओं की दशा में सुधार के साथ-साथ उनकी दिशा को भी उज्ज्वल बनाने का सामूहिक संकल्प लेना होगा।

विश्व महिला दिवस पर विशेष

प्रो. मनोज कुमार
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

मध्यप्रदेश में खुलते स्त्रियों के लिए बंद कपाट

समाज में स्त्रियों के लिए बंद कपाट मध्यप्रदेश में खुल गए हैं. स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में बीते वर्षों में जो कोशिशें हुई हैं, वह पूरे देश के लिए रोल मॉडल साबित हो रहा है. स्त्री समाज की नींव मजबूत करने के लिए जरूरी होता है कि उन्हें शिक्षित किया जाए और आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाया जाए. महिला सशक्तीकरण, सुरक्षा, सम्मान और समग्र विकास के अद्वितीय कोशिशों ने महिला समाज को उजास से भर दिया है. शहरी इलाके हों या गांव-पंचायत, सभी जगहों पर महिलाओं की बुलंद आवाज सुनाई देती है. राज्य के कोने-कोने में स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को उनके हुनर के अनुरूप अवसर मिल रहा है. साथ में केन्द सरकार द्वारा महिला कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाओं ने महिलाओं को और भी संबल दिया है. इस बार विश्व महिला दिवस पर मध्यप्रदेश एक नया अध्याय लिखने जा रहा है. केन्द सरकार द्वारा लागू उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, मातृत्व वंदना योजना और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों ने करोड़ों बेटियों, बहनों के जीवन को नई दिशा दी है वहीं मध्यप्रदेश में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना सबसे क्रांतिकारी पहलों में से एक रही है। पहली नजर में लगता कहा जाता है कि महिला वोटबैंक को मजबूत करने के लिए रुपये बांटने वाली स्कीम चलायी जा रही है लेकिन जतीनी हकीकत जाँचने जाएं तो पता चलेगा कि इन रुपयो से महिला सशक्तिकरण के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं. करोड़ों रुपये महिलाओं के खातों में पारदर्शी डिजिटल अंतरण के माध्यम से प्रदान किए गए, जिसने मध्यप्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भरता की नई दिशा दी है। इस राशि से महिलाओं ने स्व-रोजगार की शुरूआत की है. पहले इस राशि से किराये की सिलाई मशीन ली गई और बाद में अपने मुनाफा से स्वयं की सिलाई मशीन खरीद ली गई. पशु पालन से लेकर किराने की दुकान जैसे अनेक कोशिशों में महिलायें सफल हुई हैं. इस आत्मनिर्भरता के चलते आहिस्ता-आहिस्ता महिलायें स्वयं में सक्षम होकर योजना से स्वयं ही बाहर होकर शेष जरूरतमंद महिलाओं को अवसर दे रही हैं. सरकार द्वारा जारी आंकड़ें इस बात की पुष्टि करते हैं. इसी तरह सात महिलाओं ने अपना समूह तैयार कर एक नए किस्म की कोशिश को अंजाम दिया है. इसे स्व-सहायता समूह कहा गया. स्व-सहायता का सामान्य रूप से अर्थ समझ सकते हैं स्वयं की सहायता करना. स्व-सहायता समूह ने सशक्तिकरण के नए आयाम छुए हैं. कल तो जिन कामों पर पुरुषों का एकाधिकार था, आज उनमें महिलाएं पारंगत हैं. बिजली ठीक करने से लेकर बैंक खाता खुलवाने और उसका परिचालन करने जैसे अनेक कार्य महिलाएं कर रही हैं. मोहन सरकार ने अनेक कार्य स्व-सहायता समूह को सौंप दिया है जो कभी पहले निजी संस्थाएं करती थीं. मोहन सरकार की इस पहल से जैसे पूरा परिदृश्य बदल

रहा है. मध्यान्ह भोजन से लेकर गणवेश बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर स्व-सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में पीएम-जनमन तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्थान अभियान के माध्यम से सैकड़ों नए आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन प्रारंभ किया गया है। इससे जनजातीय महिलाओं और बच्चों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ उनके गांवों तक उपलब्ध कराई गई हैं। हजारों भवनों के निर्माण और उन्नयन से आंगनवाड़ी व्यवस्था अधिक सशक्त और सुरक्षित बनी है। पोषण अभियान के अंतर्गत लाखों बच्चों के विकास की निगरानी के लिए अत्याधुनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं। फेस-मैच आधारित सत्यापन ने हितग्राहियों को पारदर्शी और समयबद्ध लाभ दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे अभियानों ने पोषण और पर्यावरण–दोनों आयामों को जोडक़र जनभागीदारी का नया मॉडल प्रस्तुत किया है। मध्यप्रदेश, महिला सम्मान और सुरक्षा के विषय में समाज को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। मिशन शक्ति के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटरों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पिंक ड्राइविंग लाइसेंस, जेंडर चैंपियन पहल और सशक्त वाहिनी कार्यक्रमों ने महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण को और मजबूती प्रदान की है। बीते साल में 20,332 महिलाओं को त्वरित राहत और परामर्श उपलब्ध कराया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत नवजात बालिकाओं का स्वागत, पूजा-अर्चना और व्यापक पौधारोपण ने समाज में बेटियों के सम्मान की संस्कृति को मजबूत किया है। पिंक ड्राइविंग लाइसेंस और जेंडर चैंपियंस जैसी पहलें बालिकाओं के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को नई उड़ान दे रही हैं। राज्य एवं जिला स्तर के हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन ने जनजागरूकता की दृष्टि से अभूतपूर्व कार्य किया है। 100 दिवसीय अभियान, घरेलू हिंसा निरोधक कार्यक्रम, बाल विवाह मुक्ति प्रतिज्ञा, P-C-P-NDT अधिनियम जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और आत्मरक्षा कार्यक्रमों ने समाज में व्यापक संवेदनशीलता विकसित की है।

वर्ष साल में 1.47 लाख से अधिक गतिविधियाँ आयोजित हुईं और लाखों नागरिकों की भागीदारी ने यह सिद्ध किया कि मध्यप्रदेश, महिला सम्मान और सुरक्षा के विषय में समाज को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि यहां से आरंभ की गई योजनाओं को देश के अन्य प्रदेश वैसा ही अपना लेते हैं. मातृशक्ति को लेकर मध्यप्रदेश हमेशा से संवेदनशील रहा है. महिलाओं के आमूलचूल परिवर्तन की साक्षी बनता मध्यप्रदेश को दिशा देने में लोकमाता अहिल्या देवी जैसी शासक, अवंतिबाई, रानी कमलापति जैसी साहसी और सुभदा कुमारी चौहान जैसी विदुषी महिलाओं का मार्गदर्शन है. मध्यप्रदेश हमेशा से स्त्री शक्ति का सम्मान करता रहा है और इस विश्व महिला दिवस पर हम सब स्त्री शक्ति का नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं.